www.ghoonghatkibagawat www.ghoonghatkibagawat ghoonghatkibagawat37@gmail.com

UP/HIN/1999/1282

घूँघट की बगावत

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित — हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 45 गोरखपुर, 25 मई 2025 रविवार पृष्ठ : 6 मूल्य : 2

▸ नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक संपन्न

विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य : मोदी



नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक शनिवार को हुई। गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय है 'विकसित भारत@2047 के लिए विकसित राज्य'। नीति आयोग की सर्वोच्च संस्था परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें विकास की गति बढ़ानी है। अगर केंद्र और सभी राज्य एक साथ मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।

मोदी ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा, तो भारत भी विकसित होगा। यह 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है। उन्होंने कहा कि राज्यों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तथा सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करके प्रत्येक राज्य में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करना चाहिए। एक राज्यः एक वैश्विक गंतव्य। इससे पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा। उन्होंने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ यह पहली बड़ी बैठक है। बयान के अनुसार, विकसित भारत के लिए विकसित राज्य का विचार राज्यों से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जुड़े साहसिक, दीर्घकालिक और समावेशी विजन दस्तावेज तैयार करने का आह्वान है, जो स्थानीय वास्तविकताओं पर आधारित हों। इसमें कहा गया है, इन विजनों में समयबद्ध लक्ष्य शामिल होने चाहिए। आम तौर पर, पूर्ण परिषद की बैठक हर साल होती है और पिछले साल यह 27 जुलाई को हुई थी।

देश की एकता और अखंडता पर सवाल उठाना राहुल गांधी की आदत... कांग्रेस नेता पर बरसे सिंधिया



नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आदत है कि वे देश की एकता पर सवाल उठाते हैं, भले ही भारतीय एकजुट हों। यह टिप्पणी राहुल गांधी द्वारा विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछे गए तीन सवालों के बारे में पूछे जाने के बाद आई है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि देश की एकता, अखंडता और सम्मान पर सवाल उठाना राहुल गांधी की आदत है, खासकर ऐसे समय में जब 140 करोड़ भारतीय एकजुट हैं और कुछ तत्व भारत की संप्रभुता और एकता पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ने जयशंकर से पूछे गए सवालों के समय को लेकर भी कांग्रेस नेता की आलोचना की। सिंधिया ने कहा कि यहां तक कि जब आतंकवादियों और दुश्मनों का सामना करना पड़ रहा हो? ऐसे गंभीर समय में इस तरह के सवाल उठाना-यह किस तरह की विचारधारा है? न तो आप और न ही हम इसे समझ सकते हैं। कभी गांधी के करीबी रहे सिंधिया 2018 में कांग्रेस से अलग होकर भाजपा में शामिल हो गए थे। गांधी ने शुक्रवार को जयशंकर पर निशाना साधते हुए दावा किया कि भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई है। उन्होंने कांग्रेस की एक पोस्ट को टैग किया जिसमें जयशंकर का एक वीडियो क्लिप था जिसमें वे डच ब्रॉडकास्टर एनओएस के साथ साक्षात्कार के दौरान पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत-पाक संघर्ष पर सवालों के जवाब दे रहे थे। गांधी ने कहा, ₹क्या जेजे (जयशंकर) बताएंगे कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया है? पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा?

भारत ने एयर स्पेस 23 जून तक के लिए किया बंद



नई दिल्ली। भारत ने पाकिस्तान की उड़ानों के लिए नोटम-एनओटीएएम को आगामी एक माह के लिए बढ़ा दिया है। यह 23 जून, 2025 तक प्रभावी रहेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय हवाई क्षेत्र पाकिस्तान में पंजीकृत ACFTs और पाकिस्तानी एयरलाइनों/ऑपरेटरों द्वारा संचालित/स्वामित्व वाली या पट्टे पर ली गई ACFTs के लिए स्वीकृत नहीं है, जिसमें सैन्य उड़ानें भी शामिल हैं। दूसरी ओर खराब मौसम के दौरान इंडिगो की फ्लाइट को अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देने से इनकार करने की खबर सामने आने के एक दिन बाद, पाकिस्तान ने गत शुक्रवार को भारतीय विमानवाहकों पर अपने प्रतिबंध को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है।

यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा की ज्योति कथित तौर पर हाल के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी के संपर्क में थी, जिसे हाल ही में भारत विरोधी गतिविधियों के लिये देश से निकाला गया।





भीतर के दुश्मनों के खिलाफ सख्ती-चौंकसी बढ़ानी होगी

पाकिस्तान भारत के अनेक लालची, शानोशौकत के आकांक्षी, देशद्रोही एवं देश के दुश्मन लोगों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रचार और जासूसी गतिविधियों के लिए कर रहा था। ऐसे ही कुछ देश विरोधी तत्वों का पदार्फाश होना चौंकाता भी है एवं चिन्ता में भी डालता है। ऐसे ही तत्वों में एक नाम है ज्योति मल्होत्रा, उस पर आरोप है कि वह न केवल सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश कर रही थी, बल्कि उसने पाक खुफिया एजेंसी के एजेंटों से भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां भी साझा कर रही थीं, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी गोपनीय जानकारियां भी थीं। वह एक खुफिया एजेंट के रूप में सीमा पार से चलाए जा रहे नेटवर्क का हिस्सा थी। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत की मिट्टी पर छिपे गद्दार कितनी भी चालाकी से छिप जाएं, वे कानून की नजरों से नहीं बच सकते। उम्मीद है कि पूछताछ में ऐसे सबूत मिल सकते हैं जो भारत के खिलाफ बड़ी साजिशों का खुलासा कर सके। 'ऑपरेशन सिंदूर' ने न सिर्फ सरहद पार बैठे दुश्मनों की नींद हराम कर दी है, बल्कि देश के भीतर बैठे गुप्त गद्दारों की भी कमर तोड़ दी है। हाल ही में लगातार ऐसे अनेक राष्ट्र-विरोधी जासूसों की गिरफ्तारी ने जता दिया कि भारत हर मोर्चे पर देश की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिये प्रतिबद्ध है। ये गिरफ्तारियां अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण एवं यह भी पाक की एक करारी हार ही है।

पाक के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा समेत छह लोगों की खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर की गयी गिरफ्तारी भारत की सतर्कता एवं सावधानी को तो दशार्ती ही है, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इस चुनौती भरे समय में भीतर के दुश्मनों की शिनाख्त एवं उनकी धडपकड़ कितनी जरूरी है। ट्रैवल विद जो नाम से यू-ट्यूब चैनल चलाने वाली ज्योति पर आरोप है कि वह पाक के कई उच्च अधिकारियों के संपर्क में थी और भारत से जुड़ी गुप्त सूचनाएं पाक तक पहुंचाती थी। पता यह भी चला है कि पाक यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात पाक उच्चायोग के एक कर्मचारी दानिश से हुई, जिसके माध्यम से उसकी पहचान आइएसआइ के एजेंटों से हुई। ज्योति इन एजेंटों के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचौट के जरिये संपर्क में थी। कहते हैं कि उसने एक पाक खुफिया अधिकारी के साथ गहरे संबंध बनाये और उसके साथ बाली भी गयी थी। ज्योति एवं उसके सहयोगी बेखौफ भारत की अति-संवेदनशील एवं गोपनीय सूचनाओं को पाक से साझा करते हुए देश को नुकसान पहुंचा रहे थे। ये सभी आम नागरिकों की तरह जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इनके इरादे राष्ट्रविरोधी थे। देश की कीमत पर सारे राष्ट्र-मूल्यों एवं निष्ठाओं को ताक पर रखकर धनार्जन की लालसा और मौज-मस्ती का लक्ष्य घिनौना एवं अक्षम्य अपराध है। राष्ट्र को इन विस्फोटक विसंगतियों से बचाना होगा।

भारत विरोधी शक्तियों के हाथ में खेलकर देश को मुश्किल में डालने का यह कृत्य परेशान एवं चिन्ता में डालने वाला है। बहुत संभव है कि जासूसी कांड में लिप्त ये भारतीय बड़े आर्थिक प्रलोभनों के लालच में पाक एजेंटों के जाल में फंसे हों। लेकिन बड़ा प्रश्न है कि कैसे कुछ लोग पैसे व शानोशौकत के लालच में देश की सुरक्षा व लोगों का जीवन भी दांव पर लगा सकते हैं? देश के भीतर के ये दुश्मन बाहरी दुश्मनों से ज्यादा घातक एवं नुकसानदेय हैं। पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई से ताल्लुक रखने पर पिछले दिनों हरियाणा, पंजाब व यूपी के इन लोगों की गिरफ्तारी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। लेकिन इनकी गहन जांच से और भी गंभीर खुलासे होने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। ये एक गंभीर चुनौती है और हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों और खुफिया संस्थाओं को अब इस चुनौती को गंभीरता से लेना होगा। इन लोगों के तार भीतर कहां-कहां जुड़े है, इसका पदार्फाश होना ज्यादा जरूरी है। ये तत्व देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही सांप्रदायिक सद्भाव एवं आम-जनजीवन को भी खतरे में डाल सकते हैं।

यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा की ज्योति कथित तौर पर हाल के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी के



संपर्क में थी, जिसे हाल ही में भारत विरोधी गतिविधियों के लिये देश से निकाला गया। इस मामले में चल रही जांच से पता चला है कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले से पहले ज्योति कश्मीर गई और उससे पहले पाकिस्तान गई थी। एक से अधिक बार पाकिस्तान जा चुकी ज्योति पर खुफिया अधिकारियों की नजर तो थी ही, ज्योति के कई वीडियोज ने भी खुफिया एजेंसियों का ध्यान खींचा, चाहे वह नयी दिल्ली स्थित पाक दूतावास में इफ्तार की दावत का वीडियो हो, पिछले साल हुए विश्व कप में भारत-पाक मैच में दर्शकों की प्रतिक्रिया वाला वीडियो हो या कश्मीर घूमने आये लोगों पर बनाये गये वीडियो हों। विडंबना है कि पाकिस्तान भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत फायदा उठा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, ज्योति को दुबई के एक कथित हैंडलर के माध्यम से भुगतान किया जाता था।

यह खुलासा केवल ज्योति तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि इसके जरिये एक बड़े नेटवर्क का पदार्फाश हुआ है उस पर पाक के खुफिया अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप हैं। यूपी के रहने वाले शहजाद और नौमान इलाही पर भी इसी तरह के आरोप हैं। पंजाब में मालेरकोटला के दो लोगों को भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों को पता लगाना होगा कि क्या इन आरोपियों की सैन्य या रक्षा अभियानों से संबंधित जानकारी तक सीधी पहुंच थी या वे इसे उच्च पदस्थ स्त्रोतों से प्राप्त कर रहे थे? इन बातों का खुलासा होना सुरक्षा एवं सैन्य गोपनीयता की दृष्टि से ज्यादा जरूरी है। गिरफ्तार सभी अपराधियों को गंभीर पूछताछ के बाद कठोर सजा मिलनी चाहिए। दुश्मन चाहे देश के अंदर हो या बाहर उनके प्रति मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति निरंतर सख्ती के साथ कार्यरत रहनी ही चाहिए। सरकार और खुफिया एजेंसियां अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय संदिग्ध तत्वों की निगरानी और जांच को और तेज करने की दिशा में स्वाभाविक ही काम कर रही है। सरकार ने इन गिरफ्तारियों के बाद स्पष्ट संदेश दिया है कि राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत अब तक देशभर में दर्जनों संदिग्धों को निगरानी में लिया गया है और जांच तेज है।

निश्चय ही यह राष्ट्र-विरोधी जासूसों का खुलासा पाक रचित राष्ट्रघाती खेल का छोटा हिस्सा है, पाक सीधा युद्ध की सामर्थ्य एवं ताकत नहीं रखता, इसलिये कभी वह आतंक का सहारा लेता है तो कभी पैसों का प्रलोभन देकर देश के लोगों को खरीदने की कुचेष्ठा करता है। एक छलकपट वाले सूचना युद्ध के माध्यम से देश को नुकसान पहुंचाने की आईएसआई की साजिश को सख्ती से नाकाम किया जाए ताकि आने वाले समय में और बड़ी मछलियां इस दलदल में पकड़ी जा सकेंगी। पाक तो भारत का शत्रु है और वह सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन देश के अंदर छिपे गद्दार भी भारत के शत्रु हैं। इस तरह के गद्दारों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पाक का समर्थन करने वाले खालिस्तानी आतंकवादी हैं, कश्मीर में भी ऐसे लोग है जो पाक एवं उसके पोषित आतंवादियों का सहयोग एवं समर्थन करते हैं। ऐसे राष्ट्र-विरोधी लोगों एवं आतंकवादियों का सिर कुचलने का, यही सही समय है। केंद्र व राज्य सरकारों, मीडिया और जनता को मिलकर ऐसे तत्वों को बेनकाब करने में मदद करनी चाहिए। पुलिस को आधुनिक उपकरणों के साथ इस बाबत कुशल प्रशिक्षण देना चाहिए। बहरहाल, देश विरोधी तत्वों की निगरानी तेज करना वक्त की जरूरत है। ताकि देश मे छुपी इन काली भेड़ों एवं देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे शत्रुताओं का नाश किया जा सके।



– ललित गर्ग

केरल में 16 वर्षों में पहली बार मानसून ने समय से पहले दी दस्तक

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (क्टऊ) ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून शनिवार (24 मई) को केरल पहुंचा, जो 2009 के बाद से भारतीय मुख्य भूमि पर सबसे पहले दस्तक देने वाला है। 2009 में 23 मई को मानसून की शुरूआत हुई थी। आम तौर पर, दक्षिण-पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल में दस्तक देता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। यह 17 सितंबर के आसपास उत्तर-पश्चिम भारत से पीछे हटना शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस चला जाता है। क्टऊके आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल 30 मई को दक्षिणी राज्य में मानसून पहुंचा था; 2023 में 8 जून को; 2022 में 29 मई को; 2021 में 3 जून को; 2020 में 1 जून को; 2019 में 8 जून को; और 2018 में 29 मई को।

दक्षिण-पश्चिम मानसून, जो भारत में वार्षिक वर्षा का 75 प्रतिशत से अधिक लाता है, ने केरल तट पर अपनी शुरूआत की है, जो पिछले 16 वर्षों में इसका सबसे पहले आगमन है। पिछली बार यह इतनी जल्दी 2009 में आया था, जब यह 23 मई को भारतीय तट पर पहुंचा था। पिछले सप्ताह से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश के



साथ दक्षिणी प्रायद्वीप में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, केरल-माहे और कर्नाटक में 27-29 मई तक व्यापक बारिश जारी रहने की संभावना है। अगले पांच दिनों में तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में भी भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है, खासकर 25 और 26 मई को अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी है।

मौसम विज्ञानियों के अनुसार, शुरूआत की तारीख और मौसम के दौरान देश भर में कुल वर्षा के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। केरल में जल्दी या देर से आने वाले मानसून का मतलब यह नहीं है कि यह देश के अन्य हिस्सों को भी उसी तरह कवर करेगा। यह बड़े पैमाने पर परिवर्तनशीलता और वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय विशेषताओं की विशेषता है।

अप्रैल में आईएमडी ने 2025 के मानसून सीजन में सामान्य से अधिक संचयी वर्षा का अनुमान लगाया था, जिससे अल नीनो की स्थिति की संभावना को खारिज कर दिया गया था, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य से कम वर्षा से जुड़ी है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 1.7 डिग्री कम है। क्टऊने शनिवार और रविवार को बारिश के साथ आंधी का अनुमान लगाया है, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। शनिवार को सुबह 8:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 62 प्रतिशत दर्ज की गई।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता मध्यम थी, जिसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक 120 था। सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है।

पुंछ में पीड़ितों से मिले राहुल गांधी



पुंछ । लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पुंछ के एक स्कूल का दौरा किया और पाकिस्तान की सीमा पार से हो रही गोलाबारी से प्रभावित छात्रों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब, आपने खतरा और थोड़ी भयावह स्थिति देखी है, लेकिन चिंता न करें, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने का आपका तरीका यह होना चाहिए कि आप खूब पढ़ाई करें और खूब खेलें और स्कूल में ढेर सारे दोस्त बनाएं। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह बहुत बड़ी त्रासदी थी और इसमें कई लोगों की जान चली गई। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने लोगों से बात की और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का अनुरोध किया है और मैं ऐसा करूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस महीने की शुरूआत में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सीमा पार से की गई गोलाबारी के पीड़ितों से मिलने के लिए शनिवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले का दौरा किया।

एक देश-एक चुनाव: विरोध करने वालों के तर्क स्पष्ट नही



देहरादून ।एक राष्ट्र-एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए इसे जरूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस पर विरोध करने वालों के तर्क स्पष्ट नहीं हैं।

दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आई जेपीसी ने बुधवार को मसूरी रोड स्थित होटल में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, एनटीपीसी, एनएचपीसी, टीएचडीसी और आरईसी जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधियों के साथ भी एक साथ चुनाव के विषय पर चर्चा कर और उनकी राय जानी।इस दौरान मीडिया से बातचीत में जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि देश में वर्ष 1967 तक 15 साल एक साथ चुनाव हुए, उससे कोई अराजकता नहीं फैली। जिन राज्यों में अभी भी लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वे खुश हैं। जो लोग या दल विरोध कर रहे हैं, वह उसे स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं।

चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव होने पर सबसे बड़ा फायदा लोकतंत्र की मजबूती का होगा। मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोचना है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहें तो हमारे मतदाताओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बार-बार चुनाव, फ्री राशन, फ्री बिजली...जैसे मुद्दों पर इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस में सुप्रीम कोर्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन के खिलाफ मान चुका है। वोटर को राशन नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य का प्रलोभन देना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीब आदमी मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। प्रधानमंत्री की यही सोच है, तभी भारत विकसित बनेगा।

समिति कल इनसे करेगी चर्चा

बृहस्पतिवार को समिति सबसे पहले राज्य के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन के साथ गृह, वित्त, विधि, शिक्षा विभागों के प्रमुखों, पुलिस महानिदेशक के साथ चर्चा करेगी। दोपहर बाद बार काउंसिल के पदाधिकारियों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, आईआईटी रुड़की के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी और उनके सुझाव लेंगे। स्थानीय स्तर की प्रमुख हस्तियों के साथ चर्चा के लिए भी एक सत्र निर्धारित किया गया है। बुधवार को सुबह समिति सदस्यों ने एक घंटा योग भी किया।

गढ़वाल सांसद एवं संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य अनिल बलूनी ने कहा कि वे सभी हितधारकों, राजनीतिक दलों, प्रशासनिक, स्थानीय सेलिब्रिटी से बातचीत कर रहे हैं। एक देश- एक चुनाव पर उनकी राय ली जा रही है। उत्तराखंड में भी इसी हिसाब से बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा कि देश में उत्साह है।

एक देश-एक चुनाव होगा तो उसके फायदे होंगे। केंद्र सरकार लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है। जब बिल संसद में आया तो विपक्ष ने जेपीसी के गठन की मांग की। सरकार ने स्वीकार किया। अब जेपीसी पूरे देश में लोगों से बातचीत कर रही है। अन्य राज्यों में भी जाएंगे। उत्तराखंड राज्य के लिए एक देश एक चुनाव महत्वपूर्ण है। दुर्गम इलाके होने के कारण यहां ज्यादा संसाधन लगते हैं। समिति जहां जा रहा है वहां इसे लेकर सकारात्मक माहौल है। लोगों में इसे कानून बनाकर जल्द लागू करने की जिज्ञासा है।

एटीएस ने किया बड़ी साजिश का पर्दाफाश



मुरादाबाद । उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वॉड ने एक बड़ी साजिश का पदार्फाश करते हुए मुरादाबाद से गिरफ्तार किए गए शहजाद नामक व्यक्ति के खिलाफ सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में पता चला है कि शहजाद भारत में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। खुफिया एजेंसियों को जब इस बारे में सूचना मिली, तो उन्होंने उसकी निगरानी शुरू की और अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

एटीएस सूत्रों के अनुसार, शहजाद अकेले काम नहीं कर रहा था। उसने रामपुर के कई युवाओं को पाकिस्तान भेजा था, जहां उन्हें जासूसी और विध्वंसकारी गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन युवाओं के वीजा की व्यवस्था खुद शहजाद ने की थी, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंटों की सीधी मदद मिली। सूत्रों के मुताबिक ये वीजा नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के माध्यम से जारी किए गए। शहजाद के संपर्क में दानिश नाम का आईएसआई एजेंट था, जो उच्चायोग में तैनात था और वीजा दिलवाने में अहम भूमिका निभा रहा था। दानिश का ही नाम पहले हरियाणा की ज्योति मेहरोत्रा को पाकिस्तान भेजने के मामले में भी सामने आ चुका है, जिसे पहले ही जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में यह भी सामने आया है कि शहजाद का आईएसआई से संपर्क पहले तस्करी के दौरान हुआ था। बाद में व्हाट्सएप जैसे एन्क्रिप्टेड माध्यमों के जरिए बातचीत होती रही। आईएसआई के एजेंटों ने शहजाद को भारत से संवेदनशील सूचनाएं भेजने का निर्देश दिया, ताकि आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके और देश में अशांति फैलाई जा सके। शहजाद ने बेहद चालाकी से रामपुर के कुछ भोले-भाले युवाओं को अपने नेटवर्क में शामिल किया और उन्हें कॉस्मेटिक, नकली आभूषण और महिलाओं के कपड़ों की तस्करी जैसे कामों में लगाकर वैध व्यवसाय का दिखावा किया। धीरे-धीरे उन्हें मानसिक रूप से तैयार कर पाकिस्तान भेजने की व्यवस्था की गई। एटीएस को संदेह है कि इन युवाओं को पाकिस्तान में कट्टरपंथी प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें भारत में सूचना व धन के लेन-देन के लिए इस्तेमाल किया गया। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान से आने वाला पैसा देश के अंदर अलगाववादी और विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने में खर्च किया जा रहा था। शहजाद को अब न्यायिक हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिससे इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आईएसआई एजेंटों की जानकारी मिल सके. उसके मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है, ताकि यह पता चल सके कि उसे किससे कितनी रकम मिली और उसने किसे दी।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद 'आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस' की नीति को वैश्विक पेटल पर रखेगा भारत



शशि थरूर रविशंकर प्रसाद संजय झा बैजयंत पांडा कनिमोझी सुप्रिया सुले श्रीकांत शिंदे

नई दिल्ली। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी मजबूत नीति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने और पाकिस्तान के आतंकवादी मंसूबों को बेनकाब करने के लिए एक व्यापक राजनयिक अभियान शुरू किया है। इसके तहत 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को 33 देशों में भेजने का फैसला किया गया है, जो 21 मई से 5 जून 2025 तक विभिन्न देशों का दौरा करेंगे। इस अभियान का मकसद पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की 'आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस' की नीति को दुनिया के सामने रखना है।

बता दें कि आज 2 डेलिगेशन रवाना होने वाले हैं। पहला डेलिगेशन आज जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के नेतृत्व में आज जापान के लिए रवाना होगा। ये डेलिगेशन इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, और सिंगापुर का दौरा करेगा। दूसरे डेलिगेशन का नेतृत्व शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल आज सबसे पहले वअए पहुंचेगा।

इसके बाद कांगो, सियरा लियोन और लाइबेरिया जाएगा। तीसरा डेलिगेशन 22 मई को डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में 22 मई को पहले रूस के लिए रवाना होगा। उसके बाद स्लोवेनिया, ग्रीस और लात्विया होते हुए 31 मई को स्पेन जाएगा।

बता दें कि आज, 21 मई को एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के लिए रवाना हो रहा है।

इस प्रतिनिधिमंडल या डेलिगेशन में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, अतुल गर्ग, मनन कुमार मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री एसएस अहलूवालिया, क्त्रटछ सांसद ईटी मोहम्मद बसीर, बीजद सांसद सस्मित पात्रा और पूर्व राजनयिक सुजान चिनॉय शामिल हैं। यह दल यूएई के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (24 मई), सियरा लियोन (28 मई) और लाइबेरिया (31 मई) का दौरा करेगा।

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को 7 समूहों में बांटा गया है, जो मध्य पूर्व, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, आ-स्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाएंगे। इनका नेतृत्व बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, बैजयंत पांडा, जदयू सांसद संजय झा, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, डीएमके सांसद कनिमोझी, एनसीपी (शरद पवार) सांसद सुप्रिया सुले और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं।

प्रत्येक समूह में 7 से 8 सांसद और पूर्व राजनयिक शामिल हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य देशों सहित अन्य महत्वपूर्ण देशों में भारत का संदेश पहुंचाएंगे।

प्रतिनिधिमंडल 3 और 6 का शेड्यूल

प्रतिनिधिमंडल 3: जदयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में यह दल 22 मई को जापान, 24 मई को दक्षिण कोरिया, 27 मई को सिंगापुर, 28 मई को इंडोनेशिया और 31 मई को मलेशिया जाएगा। इसमें बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी, बृजलाल, प्रदान बरुआ, डॉ. हेमांग जोशी, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और राजनयिक मोहन कुमार शामिल हैं।

प्रतिनिधिमंडल 6: डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में यह दल 22 मई को रूस, 25 मई को स्लोवेनिया, 27 मई को ग्रीस, 29 मई को लातविया और 31 मई को स्पेन जाएगा। इसमें समाजवादी पार्टी के राजीव राय, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद, बीजेपी के कैप्टन बृजेश चौटा, राजद के प्रेमचंद गुप्ता, आप सांसद अशोक कुमार मित्तल और राजनयिक मंजीव पुरी व जावेद अशरफ शामिल हैं।

मंगलवार को विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने 3 प्रतिनिधिमंडलों को ब्रीफ किया। उन्हें पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की ओर से सीजफायर की मांग तक की पूरी जानकारी दी गई। प्रतिनिधियों को बताया गया कि वे विश्व समुदाय के सामने पाकिस्तान के आतंकवाद से जुड़े 40 साल के इतिहास को उजागर करें, जिसमें 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत द्वारा दिए गए डीएनए साक्ष्य और कॉल रिकॉर्ड जैसे सबूतों पर पाकिस्तान की निष्क्रियता शामिल है।

कांग्रेस ने प्रतिनिधिमंडल के चयन पर आपत्ति जताई है।

पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने चार नाम सुझाए थे- आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और राजा ब्रार, लेकिन केवल आनंद शर्मा को शामिल किया गया। शशि थरूर को शामिल करने पर भी कांग्रेस ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है, न कि पार्टी की आधिकारिक राय।

पाकिस्तान ने भी भारत के इस कदम का जवाब देने के लिए पीपुल्स पार्टी नेता बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है, जो विश्व मंच पर अपनी 'शांति की बात' रखेगा। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का यह वैश्विक अभियान आतंकवाद के खिलाफ उसकी दृढ़ नीति को दर्शाता है।

7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 33 देशों में जाकर न केवल पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क को बेनकाब करेंगे, बल्कि वैश्विक समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान भी करेंगे।

आप ने लांच की नई एएसएपी पार्टी



नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी अब देशभर में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। युवाओं और छात्रों को राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करने के मकसद से गत मंगलवार को पार्टी ने अपने छात्र संगठन एएसएपी (एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स) की शुरूआत की। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और अवध ओझा भी मंच पर मौजूद थे।

इस मंच से केजरीवाल ने घोषणा की, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज आम आदमी पार्टी का छात्र संगठन एएसएपी अस्तित्व में आया है। यह केवल एक संगठन नहीं, बल्कि एक आंदोलन है, जो देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बदलने की ताकत रखता है। केजरीवाल ने अपने भाषण में वैकल्पिक राजनीति की व्याख्या करते हुए कहा कि देश में आज भी बुनियादी समस्याएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। उन्होंने कहा, 75 सालों बाद भी हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए हैं, और इसकी जड़ हमारी मौजूदा राजनीति है।

अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए कहा कि दोनों की राजनीति में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, आज देश में यह तय करना कि आपके घर में बिजली आएगी या नहीं, या आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी या नहीं सब राजनीति से तय होता है। इस राजनीति से भाग नहीं सकते, इसमें शामिल होना ही पड़ेगा।

उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 10 वर्षों में और अब पंजाब में सरकार चलाकर दिखा दिया है कि वैकल्पिक राजनीति कैसे काम करती है।

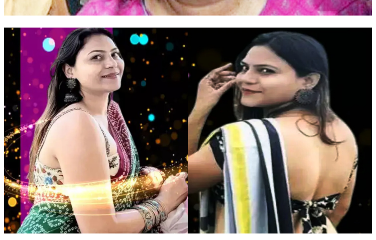
केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद की स्थिति को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, हमने फीस न बढ़ने देने की बात की थी, लेकिन बीजेपी की सरकार बनते ही तीन महीने में स्कूल फीस में इजाफा कर दिया गया। सरकारी स्कूलों की हालत बिगड़ती जा रही है और शिक्षा माफिया फिर से हावी हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि पहले बिजली 24 घंटे मिलती थी, लेकिन बीजेपी के आते ही फिर से पावर कट शुरू हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नेता अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं और हमारे बच्चों को धर्म के नाम पर आपस में लड़ाते हैं।

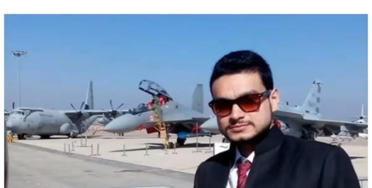
केजरीवाल ने भ्रष्टाचार और पूंजीवादी राजनीति को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक सड़क के निर्माण में 250 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए, लेकिन उसकी गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य हर एक पैसा जनता की भलाई में खर्च करना है, यही असली राजनीति है। अंत में उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए झूठ और डर का सहारा लेना, विपक्ष को जेल में डालना ये सब मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स की निशानियाँ हैं। इसके विपरीत अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मतलब है पारदर्शिता, ईमानदारी और जनता की सेवा।

ये हैं देश कि आंतरिक दुश्मन









नई दिल्ली। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के मामले ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। पुलिस का कहना है कि ज्योति मल्होत्रा के संबंध पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के साथ थे। वह उस वक्त भी पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी के संपर्क में थी, जब भारतीय सेना ने आतंकियों के खात्मे के लिए पाकिस्तान और पीओके में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ज्योति मल्होत्रा कई बार पाकिस्तान जा चुकी है। एक बार वह चीन भी गई थी।

ज्योति मल्होत्रा 'ट्रैवल विद जेओ' नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाती है। उसके कुछ वीडियो भी पुलिस के शक के दायरे में हैं। फिलहाल पुलिस हर एंगल से उसकी जांच कर रही है। देश की सुरक्षा का सौदा कर, पाकिस्तान के जाल में फंसने वाली ज्योति पहली जासूस नहीं है। आइए, आपको बताते हैं कि ज्योति से पहले कौन-कौन महिलाएं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की जासूस बनकर हमारे देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर चुकी हैं।

माधुरी गुप्ता

अप्रैल 2010 में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में तैनात एक सीनियर राजनयिक माधुरी गुप्ता को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी क्त्रकके लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। माधुरी गुप्ता कोई नई राजनयिक नहीं थी। 1980 के दशक में वह विदेश मंत्रालय में ग्रेड बी कैडर के तौर पर काम कर चुकी थी। वह उन सपोर्ट स्टाफ में से थी, जो पर्दे के पीछे रहकर भारत के राजनयिक कार्यों में मदद करते हैं।

माधुरी गुप्ता लगभग तीन दशकों तक इराक, लाइबेरिया, मलेशिया और क्रोएशिया जैसे भारतीय मिशनों में काम कर चुकी थी। उर्दू भाषा पर अच्छी पकड़ होने के कारण 2007-2008 में उसे इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में सेकंड सचिव (प्रेस और सूचना) के पद पर नियुक्त किया गया। उस-के पद का नाम भले ही बड़ा था, लेकिन उसका असली काम उर्दू प्रेस पर नजर रखना और वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों के लिए मीडिया में होने वाले घटनाक्रमों की जानकारी देना था। इससे राजनयिकों को भारत के बारे में मीडिया में क्या कहा जा रहा है, यह समझने में मदद मिलती थी।

माधुरी गुप्ता ने शादी नहीं की थी और भारत में उस-का कोई परिवार भी नहीं था। एक भाई था, जो अमेरिका में रहता था। साल 2009 के आखिर में, भारतीय खुफिया अधिकारियों को उसकी गतिविधियों में कुछ गड़बड़ दिखाई दी। माधुरी प्रेस और सूचना विंग में तैनात थी, लेकिन खुफिया अधिकारियों ने देखा कि उसने कुछ स्थानीय पत्रकारों और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ घनिष्ठ संबंध बना लिए हैं। तफ्तीश हुई तो पता चला कि माधुरी क्त्रक के अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी दे रही थी। इसके बदले में उसे पैसे और दूसरे फायदे मिल रहे थे। इस मामले के सामने आने के बाद भारत सरकार ने माधुरी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर जासूसी और देशद्रोह के आरोप लगाए गए। निचली अदालत में मुकदमा चला और दोषी करार देते हुए उसे तीन साल की सजा सुनाई गई। हालांकि, हाईकोर्ट में अपील के कारण उसकी सजा निलंबित कर दी गई। मई 2021 में माधुरी गुप्ता का निधन हो गया।

दामिनी के जाल में फंसा रंजीत

29 दिसंबर 2015 में भारतीय एयरफोर्स के जवान रंजीत केके को भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। केरल के रहने वाले रंजीत को दामिनी मेकनॉट नाम की महिला ने पत्रकार बनकर सोशल मीडिया पर अपने जाल में फंसाया था। दामिनी ने रंजीत को हनी ट्रैप में फंसाकर कई खुफिया जानकारी हासिल की थी।

पूनम बाजवा और सुनीता

अक्तूबर 2023 में राजस्थान पुलिस ने नरेंद्र कुमार नाम के एक 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। नरेंद्र सोशल मीडिया पर पूनम बाजवा और सुनीता नाम की दो पाकिस्तानी महिलाओं के हनी ट्रैप में फं-सकर, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। वह बीकानेर के बॉर्डर इलाके और उसके आसपास की जरूरी जानकारी इन दोनों महिलाओं के साथ शेयर करता था।

पेशे से मैकेनिक नरेंद्र ने बताया कि वह दो साल पहले फेसबुक के जरिए पूनम बाजवा और सुनीता नाम की दो महिलाओं के संपर्क में आया था। नरेंद्र ने पुलिस को बताया कि पूनम ने उससे कहा था कि वह पंजाब के भटिंडा की रहने वाली है। उसने यह भी बताया कि वह अभी बीएसएफ में डाटा एंट्री के पद पर काम कर रही है। उसने नरेंद्र से शादी का वादा किया और बदले में उससे बॉर्डर से सटे इलाकों की जानकारी हासिल की।

पूनम ने नरेंद्र को एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा था। इस ग्रुप में वह उससे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से लगी सड़कें, पुल, बीएसएफ की पोस्ट, टावर और सेना के गाड़ियों की फोटो और वीडियो मांगती थी। इसी तरह, सुनीता नाम की एक दूसरी महिला ने नरेंद्र को बताया कि वह एक अखबार में काम करती है। उसने भी नरेंद्र से इसी तरह की खुफिया जानकारी इकट्ठा की।

सेजल ने निशांत अग्रवाल को फंसाया

जून 2024 में निशांत अग्रवाल को देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लीक करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई। निशांत ब्रह्मोस एयरोस्पेस का पूर्व इंजीनियर है।

सेजल नाम की महिला सोशल मीडिया पर निशांत से मिली और उसे हनी ट्रैप में फंसा लिया। निशांत को अपनी बातों में फंसाने के बाद सेजल ने 2017 में उसे कुछ लिंक भेजे। निशांत ने उन लिंक पर क्लिक किया और इसके बाद उसके लैपटॉप में तीन ऐप्स इंस्टॉल हो गए।

इन ऐप्स के जरिए निशांत के लैपटॉप से गोपनीय जानकारी चुराई गई। जांच में पता चला कि सेजल उस ग्रुप का हिस्सा थी, जो भारतीय रक्षा कर्मचारियों को धोखा देने के लिए डेटा और टिप्स शेयर करता था। निशांत अग्रवाल को अक्टूबर 2018 में गिरफ्तार किया गया और दोषी मानते हुए 2024 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का अंतिम संस्कार: जब पूरी क्लास फेल होती है, तो सिस्टम अपराधी होता है



हरियाणा के 18 सरकारी स्कूलों में 12वीं का रिजल्ट शून्य प्रतिशत रहा, जो राज्य प्रायोजित शैक्षिक विफलता का संकेत है। यह केवल छात्रों की असफलता नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की नाकामी है — जिसमें शिक्षक नहीं, संसाधन नहीं और जवाबदेही भी नहीं। सरकार को पहले से इन स्कूलों की हालत पता थी, फिर भी कोई सुधार नहीं किया गया। यह स्थिति शिक्षा के अधिकार के साथ धोखा है और गरीब छात्रों के सपनों की हत्या है। अब सवाल पूछना जरूरी है — वरना यह ढांचा पूरी पीढ़ी को अंधेरे में धकेल देगा।



हरियाणा के सरकारी स्कूलों से एक शर्मनाक और विचलित कर देने वाली खबर सामने आई है — 12वीं बोर्ड परीक्षा में राज्य के 18 स्कूलों का परिणाम शून्य प्रतिशत रहा। यानी पूरे स्कूल से एक भी छात्र पास नहीं हुआ। यह घटना महज कुछ छात्रों के फेल होने की बात नहीं है, बल्कि यह पूरे शिक्षा तंत्र की नंगेपन के साथ पोल खोलने वाली स्थिति है। यह सिर्फ रिजल्ट नहीं, एक पीढ़ी के सपनों की सामूहिक हत्या है।

जब शिक्षा नहीं, तो अधिकार कैसा?

हमारे संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। लेकिन जब किसी स्कूल से एक भी छात्र पास नहीं होता, तो यह सवाल उठता है कि क्या यह अधिकार महज दिखावा है? क्या हम बच्चों को सिर्फ स्कूल भेजने की खानापूरी कर रहे हैं, या वास्तव में उन्हें ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं?

हरियाणा के इन 18 स्कूलों की हालत देखकर तो यही लगता है कि शिक्षा से अधिक ह्यप्रबंधनह्न पर ध्यान है। छात्र आए या न आए, पढ़े या न पढ़े, शिक्षक हों या नहीं — इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आंकड़े सही दिखने चाहिए।

पहले से सूचीबद्ध खराब स्कूल, फिर भी कोई सुधार नहीं!

चौंकाने वाली बात यह है कि ये वही स्कूल हैं जिन्हें सरकार ने पहले से राज्य के 100 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों की सूची में डाला था। इसका अर्थ है कि शासन-प्रशासन को पहले से इन स्कूलों की बदहाली का पता था। लेकिन कोई शिक्षक नहीं बढ़ाए गए, न प्रयोगशालाएं बनीं, न ही पुस्तकालयों का संचालन सुनिश्चित किया गया।

कुछ स्कूलों में तो विज्ञान और गणित के शिक्षक ही नहीं हैं — तो फिर छात्र पास होंगे कैसे?

सरकारी स्कूल या सजा घर?

जिस विद्यालय में किताबें नहीं, अध्यापक नहीं, वातावरण नहीं — वहां बच्चों को भेजना शिक्षा नहीं, मानसिक शोषण है। आज कई सरकारी स्कूल सिर्फ ह्यमिड डे मीलह्न वितरण केंद्र बनकर रह गए हैं। क्या यही उद्देश्य था इन विद्यालयों का? शिक्षा के नाम पर सिर्फ खाना और हाजिरी ली जा रही है, बाकी कुछ नहीं।

फेल छात्र नहीं, फेल सिस्टम है

इन छात्रों को फेल कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में फेल वह शासनिक व्यवस्था है, जो शिक्षा को प्राथमिकता देने का दावा करती है पर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं करती। फेल वह नेतृत्व है, जो चुनावी रैलियों में शिक्षा की बात करता है लेकिन सत्ता में आने के बाद आंखें मूंद लेता है। फेल वह अफसरशाही है, जो अउ कमरों से फाइलों में स्कूल चलाती है।

जब नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ें, तो आम बच्चों का क्या हक?

हरियाणा के कई बड़े नेताओं और अफसरों के बच्चे विदेश या महंगे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। वे सरकारी स्कूलों की हकीकत जानते हैं, तभी तो अपने बच्चों को वहाँ भेजने का साहस नहीं करते। लेकिन गरीबों के बच्चे जो विकल्पहीन हैं, उन्हें इस बदहाल व्यवस्था के हवाले छोड़ दिया जाता है। यह दोहरा मापदंड किसी लोकतांत्रिक समाज के लिए शर्मनाक है।

सिर्फ रिजल्ट खराब नहीं, भरोसा टूटा है

जब छात्र सालभर मेहनत करें, स्कूल जाएं, आशा करें कि वे कुछ बनेंगे — और बदले में उन्हें शिक्षक ही न मिले, पाठ्यक्रम पूरा न हो, तो उनके अंदर निराशा की दीवारें बन जाती हैं। शिक्षा सिर्फ रोजगार का साधन नहीं, आत्म-गौरव और आत्म-निर्भरता की कुंजी होती है। जब पूरा स्कूल फेल होता है, तो उसका अर्थ है कि हमने उन बच्चों का भरोसा तोड़ा है।

क्या सिर्फ मिड डे मील से चलेगा स्कूल?

आज कई सरकारी स्कूलों की पहचान सिर्फ मिड डे मील तक सीमित रह गई है। अधिकारी यह सुनिश्चित करने में लगे रहते हैं कि चावल कितना आया, दाल कितनी बंटी। लेकिन यह कोई नहीं देखता कि शिक्षा का क्या हाल है? क्लासरूम में क्या पढ़ाया गया? पाठ्यक्रम पूरा हुआ या नहीं? और सबसे जरूरी — शिक्षक आए भी या नहीं?

18 स्कूल नहीं, 18 चेतावनियाँ हैं ये

ये 18 स्कूल एक अलार्म बेल हैं — चेतावनी है कि अगर अब भी हमने सरकारी स्कूलों में सुधार नहीं किया, तो यह आंकड़ा 18 से 180 हो जाएगा। आज हिसार और झज्जर हैं, कल रोहतक, यमुनानगर, भिवानी होंगे। शिक्षा का ये ढांचा धीरे-धीरे खोखला हो रहा है, और हम मूक दर्शक बने हुए हैं।

समाधान क्या है?

स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति: अतिथि शिक्षकों के सहारे स्कूल नहीं चलाए जा सकते। योग्य, प्रशिक्षित और स्थायी शिक्षक ही शिक्षा की रीढ़ हैं। **स्वतंत्र शैक्षिक ऑडिट:** हर जिले में स्कूलों की शैक्षिक गुणवत्ता की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए — केवल आधारभूत ढांचे की नहीं, शिक्षण पद्धति और परिणामों की भी।

अभिभावक भागीदारी: स्कूलों को स्थानीय समुदाय और अभिभावकों के साथ जोड़ा जाए। जवाबदेही तभी बनेगी जब समाज जुड़ाव महसूस करेगा।

राजनीतिक इच्छाशक्ति: नेताओं को सिर्फ भाषण नहीं, एक्शन दिखाना होगा। शिक्षा पर खर्च को वास्तव में प्राथमिकता देनी होगी।

डिजिटल डिवाइड पर काम: जहां संसाधन की कमी है, वहां तकनीक से पूर्ति की जा सकती है — लेकिन उसका उपयोग सुनियोजित और प्रशिक्षित तरीके से हो।

सवाल पूछना जरूरी है

आज जब पूरा स्कूल फेल हो रहा है, तब क्या यह सवाल नहीं उठता कि उस स्कूल में शिक्षक क्यों नहीं थे? सरकार ने क्या किया? विभागीय अधिकारी किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे, तो यही सिस्टम कल हमारे बच्चों को भी निगल जाएगा।

शिक्षा की हत्या पर चुप्पी नहीं चलेगी

हरियाणा जैसे राज्य, जो कृषि, खेल और सैन्य सेवा में अग्रणी हैं, वहाँ शिक्षा की यह हालत एक विडंबना है। अगर हम इस शिक्षा विनाश पर चुप रहेंगे, तो हमारी अगली पीढ़ियाँ हमें माफ नहीं करेंगी। जब नेता शिक्षा क्रांति की बात करें, तो उन्हें इन 18 स्कूलों का रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए।यह शिक्षा का अधिकार नहीं, शिक्षा से धोखा है। यह छात्रों की विफलता नहीं, सिस्टम का अपराध है। अगर अब भी हमने आँखें मूंदी रखीं, तो अगली रिपोर्ट में यह संख्या और भयावह होगी। अब समय है — बोलने का, सवाल पूछने का, जवाब मांगने का।



डॉ सत्यवान सौरभ

आज व्यापारिक दुकान बन कर रह गए विद्यालय

जो विद्यालय ज्ञान प्राप्त करने के केन्द्र होते थे आज व्यापारिक दुकान बनकर रह गये हैं। 2025 में दिल्ली के कई प्रमुख प्राइवेट स्कूलों ने बिना उचित अनुमति के फीस में भारी वृद्धि की जिसके परिणामस्वरुप अभिभावकों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। सर्वेक्षणानुसार, पिछले तीन वर्षो में भारत भर में 44 प्रतिशत अभिभावकों ने स्कूल फीस में 50 से 80 प्रतिशत तक की वृद्धि की शिकायत की. जबकि 8 प्रतिशत से 80 प्रतिशत से ज्यादा बताया। दिल्ली के कुछ स्कूलों ने 2020 से 2025 तक पैसे 45 तक की वृद्धि की जिससे वार्षिक फीस 1.4 लाख रुपए तक पहुंच गई। दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस वृद्धि की समस्या में अभिभावकों, छात्रों और नीति-निमार्ताओं के बीच चर्चा का विषय बना दिया है। स्कूलों का यह रवैया न केवल आर्थिक बोझ को बढ़ाता है, बल्कि शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता पर भी सवाल उठाता है। यह कितना प्रभावशाली होगा यह तो आने वाल समय ही बतायेगा। सरकार को डीएसईएआर, 1993 को और सख्त करना चाहिए कि सभी स्कूल फीस वृद्धि से पहले डीआर्ड से और यह सुनिश्चित चाहे वे सरकारी या निजी जमीन पर हो, अनुगति ले। नियमित ऑडिट और पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिंग अनिवार्य होनी चाहिए। फीस निर्धारण समितियों' में अभिभावकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र जैसे राज्यों के मॉडल, जहां दो साल में 15 प्रतिशत से अधिक वृद्धि के लिए तीन-चौथाई पर अभिभावको' की सहमति आवश्यक है को लागू किया आ सकता है हो । फीस वद्धि को साजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाए सभी दलों को एक जुट होकर दीर्घकालिक समाधान खोलने चाहिए। अन्य राज्यों जैसे हरियाणा और उत्तरप्रदेश में लागू उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई - कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स) आधारित समायोजन को दिल्ली में भी लागू किया जा सकता है। दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस वृद्धि की समस्या केवल आर्थिक नहीं है बल्कि सामाजिक और नैतिक भी है। यह शिक्षा के मौलिक अधिकार को कमजोर

करती है और मध्यम वर्ग के परिवारों पर अनुचित बोझ डालती है। यह वृद्धि विशेष रूप से उन स्कूलों में भी देखी गई है ।जो दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा रियायती दरों पर दी गई जमीनों पर संचालित होते हैं। इन स्कूलों को गैर-लाभकारी मॉडल पर काम करना चाहिए लेकिन कई स्कूलों ने इस नियम का उल्लंघन किया है। अप्रैल 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अंतरिम आदेश ने शिक्षा निदेशालय के उस आदेश पर रोक लगा दिए जिसमें इन स्कूलों को फीस वृद्धि के लिए पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता थी। इस फैसले ने स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि के लिए प्रोत्साहित किया जिससे अभिभावकों का गुस्सा भड़क उठा। स्कूल प्रशासन अक्सर फीस वृद्धि को उचित ठहराने के लिए परिचालन घाटे, शिक्षकों के वेतन, बुनियादी ढांचे उन्नयन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) के छात्रों के लिए सरकारी प्रतिपूर्ति में देरी कर देता है। हालांकि अभिभावक और कार्यकर्ता इस तर्क को पारदर्शिता की कमी के कारण खारिज भी करते हैं। दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम (डीएसईआर) 1973 के तहत सरकारी जमीन पर संचालित स्कूलों को फीस वृद्धि के लिए डीओई से अनुमति लेनी होती है। हालांकि कई स्कूलों में' उच्च न्यायालय के आदेशों का लाभ उठाकर इस आवश्यकता को दर किनार किया। इसके अलावा डीओई की ओर से स्कूलों के वित्तीय रिकॉर्ड की नियमित जांच में देरी और लापरवाही ने समस्या को और जटिल किया। फीस वृद्धि का मुद्दा राजनीतिक विवाद का केन्द्र बन गया है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक-दूसरे पर निष्क्रियता और निजी स्कूलों के साठ-गांठ का आरोप लगाते हैं।

दिल्ली के एक अभिभावक का कहना है कि उसकी दो बेटियों की स्कूल फीस हर महीने 36 हजार रुपए है। जो उसकी मासिक आय का लगभग आधा हिस्सा है। इस प्रकार की वृद्धि ने ज्यादातर परिवारों को तनाव में डाल दिया है। इसके अलावा स्कूलों ने उन छात्रों को परेशान करना शुरू कर दिया है जिनके अभिभावकों ने बढ़ी हुई फीस का भुगतान करने से इनकार कर दिया है।

केवल यादों के अवशेष रहते हैं दिलों में हमेशा

गुजरता हूँ जब भी कभी गांव की गलियों से
देखता हूँ खंडहर बने वह घर जो कभी आबाद थे
गिर चुके है आधे स्लेट छत के ऊपर से
लगता है जैसे झांक रहा कोई छोटी मोरी से
बन्द पड़ा है नक्काशी किया हुआ दरवाजा
कई दिन बहुत मेहनत से बनाया था लुहार ने
सांकल लगी हुई है ऊपर कुंडी से जंग लगी हुई
बहुत दिनों से खोली नहीं है किसी ने
आंगन के किनारे पड़े है सिल बत्तू
जिस पर पीसती थी घर की औरतें
कभी कुल्थ की दाल बेहड़ी रोटी बनाने को
साथ में हरी मिर्च और धनिया बीच में डालने के लिए
रसोई के बाहर पौड़ियों के नीचे बने कोठर में
पड़ा है मिट्टी का बना पुराना सा खाली घड़ा
जो भरा रहता था हरदम पीते थे पानी घर के लोग
ढो कर लाती थी बावड़ी से घर की स्त्रियां
कहां गए वह सब लोग जो रहते थे इन घरों में
क्यों पड़े है इतने वीरान बन गए हैं खंडहर जैसे
कहां गई वह चहलपहल जो लगी रहती थी दिन भर
किसी बच्चे की किलकरियाँ क्यों सुनाई नहीं देती
ऊपर छत पर नजर आ रहा वीरान पड़ा ल्यारु
बीच में रखा है त्रियूँ जिसके ऊपर रखा है तंबैहड़
जहां जलती थी रात भर आग होती थी हंसी ठिठोली
मानो कर रहा इंतजार
उन लम्हों का कोई आए और जलाये
घर के पास खाली बन्द पड़ी है पशुशाला
तीन भैंसें बैल बकरी भेड़ें बंधी होती थी जहां
थोड़ी सी आहट पे कान खड़े हो जाते थे जिनके
मिमियाने लगती थी बकरियां रंभाने लगती थी भैंसें
अब भी नजर आ रहे
मिट्टी के बने चकन्धों के अवशेष
सड़ रहे हैं वह मोटे शहतीर टिकी थी जिन पर इमारत
एक दीवार पर उग आया है पीपल का छोटा सा पेड़
दिख रही है बहुत सारी झाड़ियां आंगन में
क्या कोई आएगा बीते दिनों को लौटाएगा
वही खुशियां चहलपहल लौटेगी क्या फिर से
नहीं यह सम्भव नहीं बीता
वक्त कभी लौटा नहीं करता
केवल यादों के अवशेष रहते हैं दिलों में हमेशा



रवींद्र कुमार शर्मा
घुमारवीं
जिला बिलासपुर हि प्र

शीतला सिंह कठोर, जटिल और बीहड़ संपादक रहे'

शीतला सिंह अपने सिद्धांतों में उतने ही कठोर, जटिल और बीहड़ रहे। उन्हें कोई डिगा नहीं सकता, यहां तक कि घर मित्र परिवारिक संबंधी और रिश्ते नातेदार भी नहीं है। दुनियां के 15-16 देशों की यात्रा और देश के विभिन्न हिस्सों में जाते रहने देखने तथा लोगों मिलने के बाद भी फैजाबाद पहुंचने पर 'जनमोर्चा' के लिए व्याकुलता बनी रहती। कई बार ऐसा होता था कि जो व्यक्ति ट्रेन से उन्हें लेने आता था। उतने दिनों का अखबार साथ लेकर जाता था तबसे वे बाहर रहा करते थे। गाड़ी में बैठने से लेकर घर पहुंचने तक सारे अखबारों को उलट पुलट कर देख चुके होते थे। प्रायः वे रामायण में राम के इस कथन को उद्धृत करते थे । वह अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण न रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।शीतला सिंह के संघर्षमय जीवन में आधुनिकता, विज्ञान और तकनीक के प्रति इतनी ललक रही कि फैजाबाद-जैसी छोटी जगह और पिछड़े क्षेत्र में भी आधुनिक संचार साधनों' के साथ जनमोर्चा का निरंतर प्रकाशन उनकी ही देन है। 1980 में बेल ऑफसेट लगाई तो एक बड़े अखबार संपादक (जो उन इ.स. दुनिया में नहीं हैं ने उन्हें सलाह दी कि - आप बेवजह यह काफी पाल रहे हैं। चला नहीं पाएंगे। मशीन बिक जाएगी। उन्होंने जवाब दिया था - भाई साहब हम गाड़ी को मैन पावर से चलाते हैं, पेट्रोल से नहीं।



शीतला सिंह संपादक भी ऐसी परिस्थितियों में बने जब तत्कालीन संपादक हरगोविंद को भारत-सुरक्षा कानून के तहत अमरीका पर लिखे संपादकीय के कारण दमनकारी नीतियों के फलस्वरूप जेल जाना पड़ा। जेल से ही उन्होंने कागज के एक छोटे पर्चे में लिखा था कि शीतला सिंह को संपादक बना दिया जाए। जेल से वापस आने के बाद भी हर गोविंद ने उसमें कोई बदलाव नहीं किया।

एक बार जनमोर्चा के वार्षिक समारोह में कामरेड के. विक्रमराव ने कहा था-पत्रकार नौकरियां करते हैं, शीतला सिंहने पत्रकारिता को सरकार करते दिखा दिया है। मुझे 35 साल एक साथ काम कसे का जो अनुभव मिला वह अपने आप में बहुमूल्य है।

लेखिका डा. सुमन गुप्ता वे। अनुसार- में शीतला सिंह से हमेशा डरती रही कि यदि मुझसे कोई गलती हुई तो उसका उन्हें दुख पहुंचेगा। एक गुड गर्ल सिंड्रोम से ग्रसित रहती हूं, जैसी मैं अपने पिता के सामने भी थी जबकि वे मुझ पर सदैव गर्व महसूस करते रहे। मैंने हमेशा कहानियों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को देख और जाना जिसे मैं बड़ी रुचि के साथ सुनती बुनती रही। शीतला प्रसाद सिंह ने कर्मा किसी कोन तो गुरु बनाया और न ही माना। वे जो कुछ भी अपने स्वाध्याय, अपनी बौद्धिक क्षमता तार्किकता और परिश्रम से ही बने। हिन्दी, अंग्रेजी संस्कृत उर्दू के साथ वेद पौराणिक ग्रंथों आदि का गहन अध्ययन किया। आर्य समाज जैसी तत्कालीन प्रगतिशील विचारधारा से ओत प्रोत विभिन्न पुस्तकों के अध्ययन ने उन्हें कम्युनिस्ट विचारधारा की ओर प्रेरित कर दिया।

अयोध्या-फैजाबाद में बहुत से राजनीतिक, धार्मिक साम्प्रदायिक उन्माद और संकट के दिन आए जिनका उन्होंने बहुत मजबूती से मुकाबला किया-वह-चाहे उन पर हमला रहा हो, अखबार पर हुआ हो। अयोध्या की घटनाएं रहीं हैं। संपादक होने के बावजूद वह एक रिपोर्टर की तरह भी घटना क्रम पर पैनी नजर रखते थे. यही कारण था कि- वह स्वयं में भी ऐसे महत्वपूर्ण मौकों पर रहते हैं। थे जहां किसी संपादक को जाने की जरुरत नहीं रहती है। उन्होंने सदा हर घटनाक्रम को बहुत ही नजदीक से अपने आंखों के माध्यम से देखने का प्रयत्न किया। चंदेरी में एक बार किसी ने उनसे पूछा था कि आप किस विश्वविद्यालय से हैं? कुछ लोग उनके लेखन भाषण और व्यक्तित्व से उन्हें डाक्टर प्रोफेसर समझने लगते हैं। उन्होंने बहुत ही सादगी से उत्तर दिया था कि मैं तो टाट-पट्टीवाले विश्वविद्यालय का बढ़ा हूं।

अब तो बहुत संपादक सप्ताह या महीने में संपादकीय लिखते हैं शीतला सिंह जब तक संपादकीय नहीं लिख लेते थे, उन्हें चेन नहीं मिलता था। हफ्ते में वह 6 दिन पूरे मनोयोग से संपादकीय लेखन करते थे।

लेखिका - डा. सुमन अतीत से बाहर निकलते हुए बताती हैं आज शीतला सिंह हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी दी हुई सीख हम लोगों के साथ है। अयोध्या मुद्दे पर हाल के सालों में बहुत सी पुस्तकें लिखी गई और बहुत सी पुस्तके लिखो भी जाएंगी। और लिखी भी जा रही हैं। ये बातें बताते हुए लेखक अरविंद कुमार सिंह ने ग्रामीण पत्रकारिता के संदर्भ में उल्लेख करते हुए शीतला सिंह के द्वारा लिखा गई पुस्तक- अयोध्याः राम जन्म भूमि- बाबरी मस्जिद का सच के माध्यम से अयोध्या का पूरा सच उजागर करती है। जिसका अध्ययन किया जाना आवश्यकता है। अगर-आधा अधूरा सच जानना हो, किस्से कहानियां पढ़ना हो तो उसके लिए बहुत सी पुस्तकों है।

अरविंद कुमार सिंह के अनुसार-शीतला सिंह का 1998 से 2004 और 2004-2014 के दौरान भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य के रूपों अनूठा कार्यकाल था। उन्होंने बहुत से क्षेत्रों में काम किया। पर वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनसे जुड़े बहुत से लोगों को यह पताही नहीं था कि वे 1959-1977 तक निर्विरोध ग्राम प्रधान रहे। उ०प्र० ग्राम प्रधान संघ के वे अध्यक्ष भी थे। 1967 से 1976 तक वे रहे। रामायण मेला समिति के वे अहम पदाधिकारी भी थे। ऐसी अनेक भूमिकाओं के कारण अनुभव का दायरा भी अधिक विस्तृत था। पत्रकारिता के लंबे दौर में उन्होंने जहां हरगोविंद और प्रदीप के साथ रह कर जहां बहुत कुछ समझा और जाना सीखा वहीं उन्हें छोटों से भी सीखने और जानने में परहेज नहीं किया।

एक ओर उनका गांव गिरांव से जुड़ाव था तो दूसरी ओर उनकी समझ वैश्विक थी क्योंकि उस दौर में जब नेपाल आना भी बड़ी बात भी तब शीतला सिंह ने रूस कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, हालैंड, बेलजियम पोलैंड, जर्मनी चेकोस्लोवाकिया, बांग्लादेश और बहुत से देशों की यात्रा कर के उसे करीब से देखा था। भारत के भाषायी समातार पत्रों के संगठन में भी उनका अनूठा योगदान रहा। वे धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव के पथिक और प्रतीक आजीवन बने रहे।

अरविंद कुमार सिंह के अनुसार - जनमोर्चा न किसी बड़ी पूंजी से निकला था न इसके पीछे बड़ा समूह था। स्वाधीनता सेनानी हर गोविंद ने 5 दिसंबर-1958 को सहकारिता के आधार पर जब इसको निकाला तो उस दौरान शीतला सिंह भी तीन स्तंभों में से एक थे। सीमित पूंजी के साथ शुरू अखबार का सीमित जीवन काल होगा ऐसी सोच भी बहुतों की रही होगी। पिछले 100 वर्षों में अयोध्या में तमाम अखबार निकले भी और काल कवलित हुए। पर जनमोर्चा न केवल डटकर खड़ा रहा, बल्कि विस्तार किया राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख भी बनाई। पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों पर काम करता रहा और अपने लक्ष्यों से कभी भटका नहीं। समाज के कमजोर तबकों की यह आज भी आवाज बना हुआ है। बहुत से ग्रामीण पृष्ठभूमि के पत्रकारों के लिए जनमोर्चा एक सशक्त मंच और प्रशिक्षण केन्द्र रहा। इन कार्यों के विस्तार के लिए और प्रशिक्षण के लिए शीतला सिंह ने अपने जीवन काल में एक ऐसी संस्था खड़ी की जिसका लाभ आज भी मिल रहा है।

ज़िंदगी की नकाबें



ऐ ज़िंदगी, तू हर रोज इक
नया चेहरा दिखा देती है,
अपनों की भीड़ में
अजनबियों-सी हवा बहा देती है।
हर रिश्ते की पोटली में कुछ भ्रम,
कुछ धोखे निकले,
हर मुस्कान के पीछे
छुपे सौ-सौ रोखे निकले।
कभी जिसको अपना समझा,
वही पराया निकला,
दिल के मंदिर में बसा देवता,
साया निकला।
तेरे इम्तिहान की हद अब महसूस होती है,
हर सुबह एक नया जख्म महसूस होती है।
कितनी बार और परखेगी, बता ओ ज़िंदगी,
कोई तो हो जो रहे बस सादगी में बंदगी।
क्या हर आंख की
नमी को तू पहचान पाएगी?
क्या सबके चेहरे से नकाब हटाएगी?
ये चुप सी शामें, ये सिसकती रातें,
हर इंसान के भीतर छुपी हैं सौ सौ बातें।
तू तो सब जानती है,
फिर अनजान क्यों बनी है?
अपनेपन की तलाश में
तू भी थकी सी लगी है।
बस अब किसी के चेहरे पे मुस्कान रहने दे,
किसी के दिल में एक मकाम रहने दे।
हर बार हर किसी को
आजमा कर थक गई होगी,
अब किसी को तो
बेनकाब अपना रहने दे, ऐ ज़िंदगी।

डॉ सत्यवान सौरभ

अफगानिस्तान की अफीम और पाकिस्तान के आतंकी भारत के लिए सिरदर्द

आज, भारत में हो रहे कुल अपराध में डेढ़ फीसदी से कुछ ज्यादा एनडीपीसी अधिनियम में दर्ज अपराध हैं। नशे के हमले का ये खौफनाक आंकड़ा है भारत के राज्यों से लगी पाक सीमा से ही नहीं देश की हर सीमा से हर तरह का नशा आ रहा है। साल 1985- में नशे पर सख्ती का कानून साल-2014 में और कड़ा किया गया था। इसके बावजूद पहले से जो व्यवस्था में नशे की लत में पड़े लोगों उन्हे अपराधी मानकर कार्रवाई होती रही है। यानी जड़ पर प्रहार करने की बजाय उसके फन को कुचला गया, जब कि नशे के काम में लिए आतंकी, भ्रष्टाचारी तंत्र में अपनी इतनी पकड़ बनाए रहे कि उन्हें कानून की तलवारें बार ही नहीं पाई। नतीजा थे कि - नशा करने वालों पर कड़ाई और धर-पकड़ में जान-बूझ बरती कोताही, सब जारी रहता है। लेकिन इन मामलों को लेकर संजीदगी और रणनीति नजर आ रही है।

2016 में उड़ा पंजाब फिल्म ने इस अपराध के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आर्थिक पक्षी की परतें उधेड़ कर बहुत दिलेरी दिखाई। फिल्में, किसी मुद्दे पर विमर्श छेड़ने का मजबूत माध्यम है। ड्रोन से नशे की तस्करी के कई मामले राजस्थान पुलिस ने पश्चिमी सीमा से हाल ही पकड़े है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू-कश्मीर, हेरोइन और गांजा के तय रास्ते हैं। नेपाल की सीमा से, उत्तर प्रदेश और बिहार में चरस गांजा की तस्करी हो रहे है। भूटान और बांग्लादेश के रास्ते आ रहा नशा, असम को नशे में डूबा रहा।म्यांमार पार कर प्रदेश वक, हेरोइन और साइकोट्रोपिक नशे की सुइयां सालों से चुभ रही है। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में कोरीन में खराश की दवाई की लत लगा दी है। यहां तक कि - समुद्री और हवाई रास्तों ऐभी तमिलनाडु और 'महाराष्ट्र के रास्ते हेरोइन की तस्करी के सारे सबूत हैं।

मणिपुर, मिजोरम नागालैंड और अरुणाचल साल 2023 में आई, इंटरनेशन नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में खुलासा हुआ कि दुनिया भर में अफीम के कुल इस्तेमाल में दक्षिण एशिया के देशों की करीब 40 फीसदी हिस्सेदारी है। और भारत इसका सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। अफगानिस्तान की अफीम और पाकिस्तान के आतंकियों के बीच का इस्तेमाल, भारत की सिरदर्दी बना हुआ है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के इलाकों में अफीम की अवैध खेती भी ये बात साबित कर रही है कि दुश्मनों के मुखौटे लगा कर बैठा है। भारत की रिसती हुई सरहदें लोभ-लालच की दुकानें हैं, जहां सीमा की हिफाजत में तैनात अफसरों, नेताओं और दलालों का अमीर भी बरसों से बिक रहा है। इसी वजह से नशे के साथ ही क्रिप्टोकरेंसी और डार्कनेट ने भी भारत को जकड़ लिया है। पिछले वर्षों में सिर्फ जम्मू-कश्मीर में पकड़ी/ पकड़े गये नशे की 26 खेप में से 14 के तार, लश्कर-ए-तैयब से जुड़े मिले। नशे के कारोबार का सीधा ताल्लुक आतंकी संगठनों से है। अब ये खुला खेल है जिसके खिलाफ भी एक आखिरी जंग की घोषणा है। हो चुकी है। सरकार अपनाई है उसमे पहली बात ये है कि नशे की चपेट में आए लोगों को अपराधी की तरह नहीं पीड़ित की तरह देखा जाता है।

बहुभाषी शिक्षा को मिले बढ़ावा

विजय गर्ग

केंद्र सरकार ने देश की भाषायी विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस पहल के तहत गर्मी की छुट्टियों में देशभर के सभी 14.5 लाख स्कूलों में 'भारतीय भाषा समर कैंप 2025' का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में बच्चों को खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी मातृभाषा के साथ-साथ एक या अधिक भारतीय भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा। यह समर कैंप एक सप्ताह का होगा, जिसमें बच्चों को भारतीय भाषाओं से जोड़ने के लिए प्रतिदिन चार घंटे की गतिविधियां संचालित की जाएंगी, जिससे कुल 48 घंटे का प्रशिक्षण होगा। कैंप के अंत में बच्चों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार के इस 'भारतीय भाषा समर कैंप का लाभ 25 करोड़ से अधिक बच्चे उठा सकेंगे।



आज के समय में रोजगार या बेहतर जीवन यापन के लिए लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। बैंक कर्मचारियों, केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षकों और आइटी क्षेत्र में कार्यरत युवाओं को अक्सर महाराष्ट्र, बेंगलुरु, हैदराबाद, तमिलनाडु या अन्य राज्यों में नौकरी के सिलसिले में जाना पड़ता है। ऐसे में उन्हें स्थानीय भाषा और संस्कृति की भिन्नता के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संवाद की कमी के कारण विवाद भी उत्पन्न होते हैं। हाल में कर्नाटक और महाराष्ट्र में ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें स्थानीय भाषा मराठी और कन्नड़ में बात करने पर जोर दिया गया है। मातृभाषा का सम्मान करना आवश्यक है, लेकिन बाहरी व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार करना उचित नहीं है। भारत एक विविधता से भरा देश है, जहां विभिन्न संस्कृतियां, धर्म और भाषाएं मिलती हैं। सभी भाषाओं का समान महत्व है, और लोगों को एक से अधिक भारतीय भाषाएं सीखनी चाहिए। इससे उन्हें किसी अन्य राज्य में जाने पर भाषा संबंधी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा । बहुभाषी लोग विभिन्न संस्कृतियों के साथ संवाद कर सकते हैं। और एक-दूसरे के विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक शोध के अनुसार, एक से अधिक भाषाएं सीखने से मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। बहुभाषी शिक्षा विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देती है, जिससे भारत में सामाजिक एकता और सद्भाव को भी बढ़ावा मिलेगा। यह भारत की भाषायी विविधता और विरासत को संरक्षित करने में मदद करेगी। अभी भी बड़ी संख्या में लोग बहुभाषी शिक्षा के लाभ से अनजान हैं। अंग्रेजी के साथ भारतीय भाषाओं को भी महत्व देना चाहिए। हालांकि बहुभाषी शिक्षा को केवल स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक विस्तारित किया जाना चाहिए।

मलोट पंजाब

पश्चिमी देश आजमी भारत को अपनी धुरी का हिस्सा नहीं मानते

भारत और पाकिस्तान जब युद्ध विराम की ओर बढ़े तभी अमेरिकी और चीनी प्रतिनिधि मंडलों ने जिनेवा में व्यापारिक युद्ध विराम के लिए बात चीत कर रहे थे। इस त्रिकोणीय महाशक्ति गतिशीलता को समझने के लिए मजबूत कुटनीति की जरूरत महसूस हो रही है। अमेरिका-ईरान के साथ सौदेबाजी और क्षेत्रीय संतुलन की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी वाताकार ईरान के साथ चौथे दौर की वार्ता को समाप्त कर रहे थे जिसमें तेहरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम सहित कई मुद्दे शामिल थे। ये घटना क्रम दशार्ते हैं कि आज की विश्व व्यवस्था निश्चित गठबंधनों से कम बल्कि व्यापार संबंधी बहुविकल्पीय समीकरणों से अधिक आकार लेती है। ट्रंप ने भारत पाक के रिश्ते को व्यापारिक सौदे की दृष्टि से समझा और युद्ध विराम का श्रेय लेने की कोशिश की जबकि दोनों देशों के बीच का टकराव सभ्यता और मूल्य आधारित है।

आज की सभ्यता अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में तीव्र गति से परिवर्तन और समायोजन हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद पुराने सभी वैश्विक समीकरण बदल गये है। पहलगाम हमले के बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ के रुख से स्पष्ट हो चुका है कि-पश्चिम आज भी भारत को अपनी धुरी का हिस्सा नहीं मानता है। इस बीच चीन ने खुल कर पाकिस्तान का साथ दिया है, जब कि भारत के पुराने दोस्त रूस का नजरिया बदल गया है। विकासित हो रही वैश्विक भू-राजनीतिक गतिशीलता से जुड़ने के लिए भारत को अपने पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान से आगे निकल कर देखना होगा। वैश्विक बहुध्रुवीयता का उदय एवं अमेरिका, चीन और रूस जैसी महाशक्तियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और ट्रेप की व्यापार संबंधी कूटनीति के समक्ष भारत को अपनी विदेश नीति को नए दृष्टिकोण से परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। जटिल सौदेबाजी और बदलने गठबंधनों को संचालित वैश्विक के व्यवस्था में भारत को रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक प्रासंगिकता को आगे बढ़ाने के लिए कुशल कुटनीतिक प्रबंधन की जरूरत है।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को भू राजनीतिक दृष्टि से समझना आवश्यक है। जहां तक पाकिस्तान स्थित आतंकी ढांचे पर भारतीय हवाई हमले हो रहे थे। वहीं मास्को में चीन रूस अपनी साझेदारी का जश्न मना रहे थे। भारत के सशस्त्र बल रुसी हथियारों के साथ और चीनी हथियारों के साथ पाकिस्तान आपसी मुकाबला कर रहे थे और हथियारों पर अभिमान कर रहे थे। वहीं, दूसरी तरफ, पुतिन और जिनपिंग ने खुद को स्टील के दोस्त घोषित किया तो आपनी राजनीति, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को और बढ़ाने का वादा किया। द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्तिकी 80वीं वर्षगांठ बनाने के लिए एकत्र हुए पुतिन और शी ने अमेरिका से अलग एक नई विश्व व्यवस्था बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसके विपरीत पुतिन ने अमेरिका के साथ सौदे की योजना भी बना ली। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों की हत्या के कुछ दिनों बाद ही कूटनीति आर्थिक सैन्य हमले सहित अन्य सभी मोर्चों पर पाकिस्तान की घेराबंदी कर भारत ने ऑपरेशन



चीन के विदेश मंत्री वांग यही ने गत 10 मई को एक वक्तव्य दिया कि चीन संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखने में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। क्वॉड देशों ने चार दिन के संघर्ष के दौरान किसी भी समय भारत की मदद नहीं की जब कि चीन की दादागिरी से जापान और ऑस्ट्रेलिया भी परेशान हैं।

सिंदूर आरंभ करते हुए पूरे पाकिस्तान के तमाम आतंकी और सैन्य अड्डों तथा एयरबेस को निशाना बनाते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया।

तथा दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है कि आज भी पाकिस्तान आतंक का वैश्विक केंद्र बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के सैन्य पराक्रम की एक मिसाल है जिससे सैकड़ों आतंकी मारे गए। भारत को इस कार्रवाई पर इस्लामिक दुनिया एक जुट होकर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी नहीं हुई। पहलगाम हमले को सबसे बड़े निंद करने वाले देशों में सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख इस्लामिक देश शामिल हुए थे। तुर्की और अजरबैजान दो प्रमुख ऐसे इस्लामी देश हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। मलेशिया के पूर्व प्रधान मंत्री महातिर मोहम्मद पाकिस्तान के पक्ष में थे। परंतु वहां की सरकार ने कश्मीर के मामले में संतुलित नीति अपनाई।

पहलगाम हमले के बाद वैश्विक महाशक्तियों और संस्थानों का रुख भारत के लिए बहुत सकारात्मक नहीं रहा है। ऐसे समय में जब पाकिस्तान का आतंकी चेहरा पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। था। उसी समय आईएमएफ जैसे- वैश्विक संस्थान द्वारा पाकिस्तान को 2.4 अरब डॉलर का बेलआउट फंड देना पश्चिमी देशों और वैश्विक संस्थाओं के आतंक के प्रति दोहरे रुख को उजागर करता है। अमेरिका के पास आईएमएफ का 16.5 प्रतिशत वोटिंग पावर है, जबकि ब्रिटेन सहित यूरोपीय संघ के पास लगभग 34 प्रतिशत है। इसके विपरीत वर्ष - 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों ने रूस को एक आक्रांता बताकर प्रतिबंध लगाए थे, जबकि पाकिस्तान का इतिहास बहुपक्षीय वित्तीय सहायता के दुरुपयोग, सैन्य विस्तार और आतंकी नेटवर्क के पोषण से जुड़ा हुआ है और भारत देशों में पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद से पीड़ित है।

प्रत्येक मोर्चे पर भारत का सहयोगी रहे उसने भी भारत और पाकिस्तान को आपसी बातचीत से अपनी असहमतियों, शिमला समझौते एवं लाहौर घोषणा पत्र के अनुरूप द्विपक्षीय तौर पर हल करने की सलाह दी जिसमें पाकिस्तान की सेना या सरकार को पहलगाम हमले के लिए दोषी आने का संकेत नहीं मिलता। अमेरिका भी पाकिस्तान को प्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी हमले के लिए दोषी नहीं समझता। यूरोपीय संघ की विदेश नीति, प्रमुख काया कलास ने संयम और स्थिति को सुधारने के लिए बात तीन का रास्ता अपनाने को कहा था। रूस और अमेरिका और यूरोपीय संघ की प्रतिक्रियाओं में एक जैसी बात दिखाई देने लगती है कि-इन्होंने भारत और पाकिस्तान को समान धरातल पर रखा गया है। वैश्विक कूटनीतिक दृष्टि से यह स्थिति भारत के लिए चिंताजनक है।

संयुक्त राष्ट्र परिषद में भी इस संबंध में चर्चा हुई। चीन क मददसे पाकिस्तान को जमीन से आतंकी गतिविधियां चला रहे थे किसी दहशतगर्द संगठन का नाम लेकर निंदा न करने की बात को पश्चिमी देशों के साथ रुस ने भी सर्व सम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर बिया है। हालांकि वर्ष 2019 तक जम्मू-कश्मीर मामले में भारत को रूस का समर्थन प्राप्त था। भारत द्वारा पुलवामा हमले के बदले फरवरी, 2019 में बालाकोट में अपनी शिविरों पर हवाई हमले का भी रूस ने समर्थन कर इसे द्विपक्षीय मुद्दे के दायरे में हो बताया था। परंतु 24 फरवरी, 2022 के बाद रूस ने यूक्रेन में विशेष कार्रवाई शुरू की थी तो भारत ने न ही निंदा की और न ही रूस पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिका और यूरोप के अभियान का हिस्सा बना बल्कि उन प्रतिबंधों से बने दबाव का पूरा लाभ उठाने की नीति अपनाई। साथ ही भारत के खतरे को लेकर पश्चिमी देशों के साथ प्राथमिकता से जुड़ा रहा है जिसका परिणाम हुआ कि राजनीतिक रूप से राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन ने जटिल भू- राजनीतिक माहौल में चीन रूस संबंधों को एक दिशा दी जिसके कारण ही पाकिस्तान भी रूस के करीब गया और ब्रिक्स समूह में शामिल करने का पाकिस्तान का प्रबल समर्थक बना।

जातिगत जनगणना : राजनीतिक दल सामाजिक न्याय के एजेंड पर एकमत होकर खड़े हों

20 24 के चुनाव के ठीक पहले तक, खासतौर से राहुल गांधी, जाति जनगणना की जरुरत पर लगातार जोर देते रहे। विपक्ष के कई नेताओं ने उनका समर्थन किया। कुछ कांग्रेस शासित राज्यों और एनडीए शासित बिहार में भी जाति जनगणना हुई। गत लोकसभा चुनाव में यह एक मुख्य मुद्दा था जिसके चलते ही चुनाव में विपक्ष की दयनीय स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ था।

भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जाति जनगणना का जबरदस्त विरोध किया था और कुल चार जातियां बतायी थी कि महिला युवा किसान और गरीब ही जाति है । जातीय जनगणना पर उन्होंने इसे शहरी नक्सल विचारधारा का हिस्सा बताया। भाजपा की पितृ संस्था आरएसएस ने कहा कि यह हिन्दू समुदाय को बांटने की एक चाल है इस पृष्ठभूमि में 30 अप्रैल 2025 को मोदी मंत्रिपरिषद ने आगामी जनगणना में जाति की गणना भी किए जाने का फैसला किया। वैसे जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन अब तक नहीं करवाई गई है. भाजपा ने इसे करवाने का फैसला इस समय क्यों किया, इस बारे में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

अनुमानतः यह फैसला जल्द ही होने वाले चुनावों, विशेषकर बिहार विधानसभा चुनाव, को ध्यान में रखकर लिया गया है। जाति जनगणना कब करवाई जाएगी और उससे प्राप्त होने वाली जानकारियों के आधार पर नीतियां बनाकर कब तक लागू की जाएंगी, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। सबसे प्रबल संभावना यही है कि इस निर्णय की वजह आगे चलकर बिहार और अन्य राज्यों होने वाले चुनावों से जुड़ी मजबूरियां हैं। यह भी साफ है कि जाति जनगणना करवाने और आरक्षण 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से बढ़ाकर और अधिक करने की बात सबसे जोरशोर से राहुल गांधी ही कर रहे थे। मतदाताओं के बड़े वर्ग ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की और यही वजह है कि आरएसएस-भाजपा गठजोड़ ने सामाजिक न्याय की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया जिसकी वे अब तक जबरदस्त खिलाफत करते थे। यह बात बेझिझक कही जा सकती है कि आर-एसएस को स्थापना मुख्यतः दलितों की सामाजिक न्याय के प्रति बढ़ती चेतना की खिलाफत के लिए की गई थी, विशेषकर, पिछली दो सदियों में सामाजिक न्याय के प्रणेताओं - ज्योतिराव फुले और उनके बाद भीमराव अम्बेडकर द्वारा इस दिशा में किए प्रयासों के बाद जैसे-जैसे दलितों में जागरूकता बढ़ती गई ऊंची जातियों में इसे लेकर बेचैनी बढ़ती गई और उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा प्रस्तुत की. यह कहने की जरूरत नहीं है कि उनके सामाजिक मूल्य मुख्यतः मनुस्मृति पर आधारित थे। आरएसएस के द्वितीय सर-संघचालक एम. एस. गोलवलकर ने मनु द्वारा निर्धारित विधियों की सराहना करते हुए कहा था कि ये अत्यंत प्राचीन हैं और इनमें वर्तमान समय के मुताबिक बदलाव करने होंगे। गांधीजी ने, विशेषकर 1932 के बाद से, जाति प्रथा के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया। उन्होंने गांव-गांव जाकर यह सुनिश्चित किया कि दलित सार्वजनिक स्थानों और मंदिरों में जा सकें और जल स्त्रोतों का उपयोग कर सकें, इन प्रयासों के प्रति आरएसएस का रवैया उदासीनता भरा रहा और उसने अपने स्वयंसेवकों और प्रचारकों को जाति एवं लिंग संबंधी ऊंच-नीच का प्रशिक्षण देना जारी रखा। सावरकर, जिन्हें आरएसएस बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता है, ने जाति प्रथा के खिलाफ कुछ प्रयास किए, लेकिन वे अत्यंत सतही थे और समय के साथ उनकी ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी की राजनीति के चलते यह मुद्दा पीछे छूट गया। भारतीय संविधान का विरोध करते हुए उन्होंने यह मत व्यक्त किया था कि मनुस्मृति ही आज का कानून है।

संविधान की खिलाफत करते हुए आरएसएस के मुखपत्र आर्गनाईजर ने कहा था कि भारतीय संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, क्योंकि इसमें उसके पवित्र

उच्च जातियां अब तक उनके हितों का संरक्षण करते आ रहे उनके पसंदीदा राजनैतिक दल द्वारा जाति जनगणना कराए जाने के फैसले से भयभीत हैं। हम जानते हैं कि देश के सामाजिक एवं राजनैतिक तंत्र में आरएसएस की जबरदस्त घुसपैठ है। वह पहले ही कह चुका है कि पिछड़े वर्गों की जनगणना का उपयोग राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।



ग्रंथ, मनुस्मृति को नजरअंदाज किया गया है। शुरूआत में उसके समर्थक वर्गों में मुख्यतः उच्च जातियां, खासकर ब्राम्हण और बनिये थे. जाति और लिंग संबधी ऊंच-नीच को मानने वाले अन्य उच्च जाति के लोगों ने भी आरएसएस का समर्थन किया। समय के साथ हिन्दुत्ववादी शक्तियों ने चुनावी मजबूरियों के चलते दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। उन्होंने दलितों के बीच कार्य करके उन्हें हिन्दू राष्ट्रवाद से जोड़ने के लिए सामाजिक समरसता मंच की स्थापना की। उन्होंने विभिन्न जातियों के हिंदू समाज में योगदान की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने इतिहास और विभिन्न जातियों की 'महानता' पर केन्द्रित पुस्तकों प्रकाशित कीं और छल पूर्वक नीची कही जाने वाली जातियों को अपने साथ लाने का प्रयास किया। हिंदू चर्मकार जाति, हिंदू वाल्मिकी जाति और हिंदू खटीक जाति ऐसी तीन प्रमुख पुस्तकें थीं जिनका विमोचन आरएसएस मुखिया मोहन भागवत ने किया और कहा कि सभी जातियां बराबर हैं। उन्होंने इन जातियों के नायकों को भी चिन्हित किया, उन्हें हिन्दू समाज के नायकों के रूप में प्रस्तुत किया और उनकी मुस्लिम विरोधी की छवि बनाने का प्रयास किया। इस रणनीति का एक उदहरण हैं राजा सुहेल देव पासी समुदाय के सुहेल देव का इस्तेमाल दलितों को लुभाने के लिए किया गया। उनके साथ सहभोजों का आयोजन किया गया और इसका उपयोग संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के भाग के रूप में किया गया। इससे आहिस्ता-आहिस्ता दलितों के कुछ वर्ग उनके साथ आए और उनके मैदानी कार्यकर्ता बन गए। कई अन्य रणनीतियां भी अपनाई गई जिनमें दलितों के बीच यह अभियान चलाना भी शामिल था कि भाजपा ऐसा इकलौता राजनीतिक दल है जो हिन्दुओं के शत्रु मुसलमानों का तुष्टिकरण नहीं करता। उन्हें आरएसएस की शाखाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया और उनमें से कईयों को महत्वपूर्ण पद दिए गए। राम विलास पासवान और रामदास अठावले जैसे कई दलित नेताओं को पद और सुख-सुविधाओं का लालच देकर लुभाया गया। चिराग पासवान ने घोषणा की कि वे मोदी के हनुमान हैं। आर-एसएस-भाजपा और सामाजिक न्याय के इम्तहान की घड़ी थी मंडल आयोग की सिफारिशों पर अमल, उच्च जातियों ने इस पर अत्यंत प्रतिकूल रवैया अख्तियार किया, यहां तक कि एक व्यक्ति ने आत्मदाह तक कर लिया। आरएसएस-भाजपा यह जानते थे कि इसका खुलकर विरोध करने पर उनकी चुनावी संभावनाओं पर बुरा असर पड़ेगा इसलिए उन्होंने ज़ुबानी तौर पर इसकी खिलाफत करने के बजाय मंडल के खिलाफ कमंडल के रूप में उससे बड़ा मुद्दा खड़ा करने की रणनीति अपनाई। उन्होंने बाबरी मस्जिद को ढहाने के अभियान में पूरी ताकत झोंक दी और वे उच्च जातियों का ध्रुवीकरण करने में सफल रहे। इसने उनके लिए चुनावों के माध्यम से सत्ता पर काबिज होने के रास्ते खोल दिए और मतदाताओं में उनकी साम्प्रदायिक राजनीति के प्रति समर्थन तेजी से बढ़ा। इस बार यह देखना दिलचस्प होगा कि वे यह कैसे सुनिश्चित कर पाते हैं कि जाति जनगणना के मुद्दे से उच्च जातियों का नुकसान न हो। उच्च जातियां अब तक उनके हितों का संरक्षण करते आ रहे उनके पसंदीदा राजनैतिक दल द्वारा जाति जनगणना कराए जाने के फैसले से भयभीत हैं। हम जानते हैं कि देश के सामाजिक एवं राजनैतिक तंत्र में आरएसएस की जबरदस्त घुसपैठ है। वह पहले ही कह चुका है कि पिछड़े वर्गों की जनगणना का उपयोग राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। वह ऐसी चालें चलने में सक्षम है जिनके माध्यम से जाति जनगणना के पक्ष में जबानी जमा-खर्च करते हुए भी सामाजिक न्याय की राह में रोड़े अटकाएं जा सकें। वक्त आ गया है कि भारतीय संविधान के प्रति गहन प्रतिबद्धता रखने वाले सभी राजनैतिक दल एक मंच पर आकर सामाजिक न्याय के एजेंडे के पक्ष में खड़े हों। जाति जनगणना के जरिए प्राप्त होने वाले आंकड़ों की रोशनी में नीतियां बनाकर उनका ईमानदारी से क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर करना एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज के निर्माण के लिए अनिवार्य होगा।



समाज में बौद्धिक की भूमिका

विजय गर्ग

बौद्धिक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बुद्धिमत्ता और विश्लेषणात्मक सोच का उपयोग पेशेवर क्षमता में या व्यक्तिगत कारणों से करता है। इसका मतलब यह भी है कि मन के उपयोग के साथ जुड़ा हुआ है या इस्-ाकी आवश्यकता है। कई तरह के बुद्धिजीवी होते हैं, उनमें से कुछ अकादमिक विरोधी होते हैं जबकि कुछ विश्वविद्यालयों का हिस्सा होते हैं. कुछ कला, राजनीति, पत्रकारिता और शिक्षा में शामिल हैं। कुछ विशेष विशेषज्ञ और पेशेवर हैं और कुछ स्वतंत्र हैं। वे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएँ प्राप्त करते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में बुद्धिजीवियों के उद्भव का पता फ्र-ांस में 'द ड्रीम्स अफेयर' में लगाया जा सकता है। बल्कि, यह अवधि सार्वजनिक जीवन में बौद्धिक के पूर्ण उद्भव के लिए उल्लेखनीय है। विशेष रूप से इस मामले पर सीधे बोलने में **mile Zola, Octave Mirbeau** और **Anatole France** की भूमिक-ाओं के साथ। बौद्धिक शब्द उस समय से बेहतर ज्ञात हो गया। फ्रेंच में संज्ञा के रूप में शब्द के उपयोग को 1898 में जॉर्जेस क्लेमेंसेउ के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

समाज में बौद्धिक की भूमिका किसी भी समाज में बुद्धिजीवियों की भूमिका वास्तव में इसके विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। बुद्धिजीवी। इसका अंदाजा ऐतिहासिक नजरिए से लगाया जा सकता है। फ्रांसीसी क्रांति को उन लोगों द्वारा उकसाया गया था जिन्हें हम आज बुद्धिजीवियों, लेनिन के रूप में वगीर्कृत करेंगे और उनके अधिकांश साथी बुद्धिजीवी थे। बुद्धिजीवियों ने परिवर्तन और शांति के लिए उत्सुक असंतोष, मोहभंग और निराश पीढ़ियों के प्रतीक बनकर मध्य पूर्व में वैचारिक संदेशों के प्रसार में सहायता की। राजनीतिक दलों और पादरियों ने बुद्धिजीवियों को अपनी संगठनात्मक शक्ति और राजनीतिक नियंत्रण बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। ऐतिहासिक रूप से आकलन करने का तरीका, किसी भी समाज पर बुद्धिजीवियों का प्रभाव उस समाज पर निर्भर करता है जिसमें वे काम कर रहे हैं: जहां नागरिक समाज कमजोर है, जहां गैर-अनुरूपता को देखा जाता है, जहां सहिष्णुता और बहुलता की कमी है, बुद्धिजीवियों को समाज को चलाने में मुश्किल होगी अधिक खुली राजनीतिक और नैतिक जलवायु की ओर। ईरानी समाज जहां इस्लाम राष्ट्रीय पहचान के निर्माण ब्लॉकों में से केवल एक है, महत्वपूर्ण बुद्धिजीवियों के लिए परिवर्तन और परिवर्तन के लिए तत्वों को वैध बनाने के लिए कई और विकल्प पेश करता है। जबकि यह कई अरब समाजों में एक ही मामला नहीं है, जहां इस्लाम है, एक तरह से या किसी अन्य अरब की विरासत से जुड़ा हुआ है और सच्ची महत्वपूर्ण सोच को रोक दिया गया है।

बौद्धिक खुद को समाज के भीतर एक विशेष गतिविधि करने के लिए समर्पित करता है जिसका अंत संस्कृति के अग्रिम के माध्यम से मानव जाति के नामांकन के बारे में लाना है। यह एक विद्वान का कर्तव्य है कि वह सत्य की खोज करने के लिए एक घृणित, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाए, ज्ञान जो विशुद्ध रूप से तर्कसंगत सिद्धांतों से प्राप्त होता है, शांति और सुरक्षित भविष्य के लिए सार्वजनिक बहस में अपनी आवाज जोड़ें। नागरिक समाज के गठन और विकास में बुद्धिजीवी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुद्धिजीवी लोकतंत्रीकरण, अधिनायकवादी शासन, तानाशाही, पश्चिमी उदारवाद, संवैधानिकता, राष्ट्रवाद, फासीवाद जैसी विचारधाराओं का भी यही आधार रहे हैं. बुद्धिजीवी आधुनिकता के सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अभिनेता हैं। महत्वपूर्ण तर्कसंगतता और नागरिक स्वतंत्रता के लिए उनका संघर्ष उनकी आलोचना और वाद्य तर्कसंगतता और वर्चस्व की भावना से इनकार के साथ हाथ में जाता है। उनकी बेहतर बौद्धिक प्रतिभा और सकारात्मक जांच की तकनीकों में प्रशिक्षण ने उन्हें स्थानीय दृष्टिकोणों की संकीर्ण अवधारणाओं को पार करने और नीति निर्माण की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने में सक्षम बनाया। नेतृत्व की स्थिति में, वे दोषरहित निष्कर्षों के आधार पर, पिछली पीढ़ियों की समस्याओं को हल करने और सामाजिक संगठन के बेहतर रूपों की स्थापना करते हैं। उन्होंने यह भी देखा कि जबकि आधुनिक समाज का पाठ्यक्रम वास्तव में अपने संगठन में अधिक तर्कसंगत बनने के लिए विकसित हुआ था, इस परिवर्तन ने व्यक्ति की अधिक स्वतंत्रता का पोषण नहीं किया, बल्कि नौकरशाही नियंत्रण के बढ़ते स्तर में योगदान दिया। इस प्रवृत्ति का एक परिणाम सामाजिक दुनिया में बढ़ती तर्कसंगतता थी, जहां मानवीय भावनाएं और विचार की पूर्व-आधुनिक आदतें प्रचलित थीं। सामंती युग की कई मान्यताएं और अंधविश्वास औद्योगिक समाज में लगातार पनपते रहे और इनमें राजनीतिक और आर्थिक विकास के पाठ्यक्रम को आकार दिया।

एक शोधकर्ता के रूप में बौद्धिक की भूमिका शोधकर्ता एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण का पीछा करते हैं और अपने विषय की जांच करते हैं। बुद्धिजीवी एक धारणा के बारे में जागरूकता विकसित करना चाहते हैं और ऐसा करते हुए वे शोधकर्ता की भूमिका प्राप्त करते हैं। वे सामाजिक वैज्ञानिक अनुसंधान में लिप्त हैं। वे अपने स्वयं के सूचित दृष्टिकोण विकसित करने में विज्ञान और पिछली परंपराओं के सिद्धांतों को लागू करते हैं। उन्होंने यह भी पाया कि सामाजिक वैज्ञानिक कार्य सामाजिक दुनिया के नवीन विश्लेषणों को बढ़ावा दे सकता है। इन शोधकताओं ने अपनी जिज्ञासाओं और विद्वानों के हितों के आधार पर अपनी जांच का आयोजन किया, ऐसा करते हुए उन्होंने कुछ तथ्यों का खुलासा किया है जो शोध नहीं होने पर चूक गए होंगे। सामाजिक दुनिया में उनकी व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि ने बड़े पैमाने पर अनुसंधान में सहायता की है। आधुनिक क्रम के तेजी से परिवर्तन के लिए चल रहे गुणात्मक रूप से अद्वितीय आकलन की आवश्यकता होती है। पुराने सूत्र स्थिर हो सकते हैं और नए विकास को समझाने की अपनी क्षमता खो सकते हैं। इस संदर्भ में बौद्धिक की भूमिका वर्तमान तक आने वाले रुझानों के संबंध में दुनिया की रचनात्मक व्याख्याओं को तैयार करना है।

विचार जो सामाजिक विचार की मुख्यधारा के अनुरूप नहीं हैं, वे वैकल्पिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में रुचि रखने वाले दूसरों की सोच में योगदान कर सकते हैं। समकालीन सामाजिक अनुसंधान, चाहे वह राजनीतिक या वैज्ञानिक किस्म का हो, अंततः दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और नैतिकता के इन दो सेटों के ढांचे के भीतर काम करने वाले बुद्धिजीवी आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के भविष्य के निदेशों को आकार देने में प्रभावशाली हो सकते हैं।

एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में बौद्धिक की भूमिका बौद्धिक भागीदारी एक राजनीतिक नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण घटक है। राजनीतिक नेताओं को सलाह देने की आधिकारिक क्षमता में काम करने वाले बुद्धिजीवी राजनीतिक नेताओं को विश्लेषण प्रदान करते हैं जो तब अपने स्वयं के विश्वासों और जिम्मेदारी की भावना के आधार पर निर्णय लेते हैं। जिस ज्ञान पर निर्णय लिए जा सकते हैं, उसके विस्तार में बुद्धिजीवी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे राजनीतिक क्षेत्र में अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं जो आगे व्यावहारिक नीति विकल्पों में अनुवादित हो जाता है। अनुसंधान और राजनीति दोनों में हाथ होने के कारण, राजनीतिक बौद्धिक सामाजिक वैज्ञानिक जांच और नीति-निर्माण के बीच महत्वपूर्ण संबंध प्रदान कर सकता है। उनका काम बड़ी समस्याओं को प्रकट करना और यह सुझाव देना है कि यह उपाय है। चूंकि नीतियां जनता के लिए बनाई जानी हैं, इसलिए बौद्धिक तरीके प्रस्तावित किए जा रहे कार्यों से लोगों के जीवन को बदलने के तरीकों में एक मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सलाहकार की जिम्मेदारी नेताओं का ध्यान उन कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों की ओर आकर्षित करना और उनके सुझाव प्रदान करना भी है। राजनीतिक बुद्धिजीवियों की अनुपस्थिति में, नीति गठन नौकरशाही उन्मुख प्रबंधकों के हाथों में आता रहेगा।

एक शिक्षक के रूप में बौद्धिक की भूमिका औद्योगिक-तकनीकी समाज में, वे जनमत को प्रभावित करते हैं और सामाजिक दुनिया के आकलन प्रदान करते हैं जो ज्ञानवर्धक हैं। शिक्षकों के रूप में उनका उद्देश्य समकालीन दुनिया की व्याख्याओं की पेशकश करना है जो प्रबुद्ध तरीके से मामलों में भाग लेने के लिए खराब सूचित व्यक्तियों की क्षमता को बढ़ाता है। इस तरह के बौद्धिक का एक और लक्ष्य अपने शिष्यों को कक्षा में और विद्वानों की बातचीत के स्तर पर गंभीर रूप से सोचना सिखाना है। उनकी शिक्षा जनता के नैतिक फाइबर को मजबूत करने और सकारात्मक जांच के निष्कर्षों में आधुनिकता की नैतिकता को बढ़ाने की पेशकश करती है। वे किसी दी गई संस्कृति की विभिन्न नैतिकता की जांच करते हैं, उनका आकलन करते हैं, और उनकी आलोचना विकसित करते हैं और ऐसा करते हुए वे एक व्यवस्थित जांच को प्रेरित करते हैं।

मलोट पंजाब

चीन पर आर्थिक प्रहार की आवश्यकता

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई के समय चीन ने पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा दिखाई दिया। चीन ने न केवल पाकिस्तान को पूर्ण समर्थन दिया, बल्कि पाकिस्तान को मिसाइलों सहित विभिन्न हथियारों की आपूर्ति भी की। दुनिया में रेखांकित हो रहा है कि चीन जिन हथियारों का पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रयोग किया बे सभी हथियार जल, थल, और नभ में मौजूद पराक्रमों और प्रभावी भारतीय सैनिकों को सैन्य व्यवस्था को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने में नाकाम रहे। वास्तविकता यह है कि-चीन अप्रत्यक्ष रूप से भारत को रूस से तेजी से आर्थिक शक्ति बनने से रोकना चाहता था। ऐसे में अब भारत द्वारा पाकिस्तान पर आर्थिक रूप से प्रतिबंधों की कड़ाई के साथ भारत के साथ शत्रुतापूर्ण आचरण कर रहे चीन से प्रतिवर्ष बढ़ते आयातों को नियंत्रित करके चीन को आर्थिक सबक दिया जाना जरूरी है।

आंकड़ों के अनुसार-चीन के साथ द्विपक्षीय कारोबार में भारत लगातार घाटे की स्थिति में है। वित्त वर्ष- 2024-25 में चीन को भारत का निर्यात 14.5 प्रतिशत घट कर 14.25 अरब डॉलर रह गया है। जबकि - वर्ष २० 23-24 में यह 16.66 डॉलर था। चिंता जनक यह है कि-चीन से वर्ष 2024-25 में आयात 11.52 प्रतिशत बढ़ कर 113.45 अरब डालर हो गया जबकि वर्ष-2023-24 में, यह 101.73 अरब डॉलर था। चीन के साथ व्यापार घटा पिछले वित्त वर्ष में करीब 11 प्रतिशत बढ़ कर 99.2 अरब डॉलर हो गया। जो वर्ष 2023- 24 में 85.81 अरब डॉलर था। चीन वर्ष 2024-25 में 127.7 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत के साथ दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा। दोनों देशों के बीच लगभग/वर्ष 2023 -24 में 118.1 अरब डॉलर का विपक्षीय व्यापार हुआ था। -चीन पर निर्भरता को कम करने के लिये जो रणनीतिक कदम उठाए गए हैं, उनका जमीनी तौर पर विशेष अर नहीं दिखा।

पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर खुला समर्थन दे रहे-चीन के साथ कोई छः महीने पहले भारत ने मित्रता की जिस राह को आगे बढ़ाया था अब उस राह को आगे रोकते हुए चीन के साथ कारोबारी असंतुलन को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने जरूरी हैं यद्यपि चीन से भारत के नए सैन्य समझौतों के बाद भारत को -चीन से आयातों को ढेर से बचने के लिए फूंक फूंककर कदम रखना जरुरी दिखाई दे रहा था लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। और चीन से आयात प्रतिमाह बढ़ते गए हैं। इसमें दो राय नहीं कि चीन पाकिस्तान को आतंकी प्रोत्साहन देते हुए भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिकी की राह में बाधक बनना चाहता है।

चीन देख रहा है कि भारत आर्थिकी को तेजी से बढ़ा रहा है और अपनी बढ़ती आर्थिक साख और आर्थिक लेखी से इसी वर्ष 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिकी बनता दिखाई दे रहा है। गत 6 मई को प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की विश्व आर्थिक परिदृश्य से जुड़ी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। इसी वर्ष 2025 के अंत तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था वाला देश बन जायेगा।

उस समय देश का सकल घरेलू आय (जीडीपी) डॉलर हो जाएगा। और यह जापान की जीडीपी बढ़कर 4.187 ट्रिलियन 4.186 ट्रिलियन डालर से ज्यादा होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है. कि - विकासकी ऊंची दर से भारत की जीडीपी वर्ष 2028 में बढ़कर 5.584 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी और भारत जर्मनी को पीछे छोड़ कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

सीजफायर: सेना के हाथ बांधने जैसा

भारत-पाक संबंधों में कडुवाहट कई दशकों से रही है। लेकिन अभी पानी सर से ऊपर जा चुका है। दोनों परमाणु शक्ति होने के नाते एक बड़ा खतरा सामने है। किसी एक ने भी इसके दुरुपयोग की दिशा में कदम उठाया तो विश्व बड़े संकट का, शिकार होगा। यही कारण है कि पहलगाम में 22 अप्रैल के आतंकी हमले में 26 निर्दोष भारतीयों के जनसंहार मामले ने बड़ा रूप धारण कर लिया। हमले में पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का हाथ होने का सहज अनुमान लगाया गया। पूरी दुनिया ने मानो इसे सच के बतौर स्वीकार भी कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से इसमें अपने आतंकी गुटों का हाथ होने से इंकार करने अथवा उनके खिलाफ कार्रवाई की पेशकश सामने नहीं आई।

ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बढ़ते दबाव के बीच अंततः बड़ा कदम देखने को मिला। भारत ने 6 मई की देर रात पाकिस्तान की सीमा में स्थित नौ आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके उन्हें ध्वस्त कर दिया। हमले में राफेल से लॉन्च की गई स्कैल्प क्रूज मिसाइलें, हैमर स्मार्ट हथियार, गाइडेड बम किट और एक्स कैलिबर गोला- बारूद जैसे आधुनिक हथियारों का उपयोग किया गया। पाकिस्तान ने इसे अपनी सीमा पर हमला मान कर जवाबी कार्रवाई की। इसके कारण दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत की जवाबी कार्रवाई में उसके 11 जवान मारे गए और 78 घायल हुए।

अगले तीन-चार दिनों तक दोनों ओर से कई तरह के हमलों की खबरें आती रहीं। साफ दिख रहा था कि यह पूर्ण-युद्ध की दिशा में बढ़ता मामला है। लेकिन दस मार्च की दोपहर अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट ने दुनिया को चौंका दिया। इसमें उन्होंने अपनी मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच सीजफायर की घोषणा की। दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रोक दिया है। इसे लेकर भ्रम की स्थिति जल्द ही खत्म हो गई क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ने कुछ ही देर के बाद भिन्न तरीकों से सीजफायर की बात कह। दी। इसके बाद भी दोनों पक्षों की तरफ से छिट-पुट हमलों की खबरें सामने आती रहीं लेकिन बड़े युद्ध की दिशा में बढ़ने के संकेत मिलने बंद हो गए।

यह कोई घोषित युद्ध नहीं था। तो युद्ध-विराम की तो बात ही नहीं उठती। सीजफायर को लेकर भी कहीं कोई चर्चा न थी। न कोई प्रस्ताव, न कोई बैठक। न कोई शर्त, न कोई समझौता । अचानक 10 मई को भारत और पाकिस्तान, दोनों की ओर से सीजफायर ने दुनिया को चौंका दिया। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वघोषित पंच की हैसियत से लगातार कई बयान देकर उलझने बढ़ा दीं। इस वजह से खास तौर पर भारत की आक्रामक छवि पर असर पड़ा। घरेलू राजनीति में विपक्ष को सवाल करने के अवसर भी मिले। यहां तक कहा गया कि इस अधपके सीजफायर से भारत का इकबाल कमजोर होता दिख रहा है। सच क्या है, इसका आकलन तथाकथित सीजफायर से जुड़े अन्य पहलुओं के सामने आने पर ही संभव होगा।

इसे लेकर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया के बीच खुद भाजपा आर आरएसएस समर्थकों के एक तबके में मायूसी देखी गई। इन चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मई की रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, इसमें उन्होंने पकिस्तान द्वारा सीजफायर की पहल किए जाने का दावा किया।उन्होंने अपने संदेश में ट्रंप या अमेरिका का कोई जिक्र नहीं किया लेकिन इससे सवालों के जवाब मिलने के बदले नये सवाल उठ खड़े हुए। हद तो यह हो गई कि मोदी के संबोधन से कुछ ही देर पहले ट्रंप ने एक नया खुलासा किया। ट्रंप ने कहा कि उन्होने दोनों देशों को व्यापार करने को पेशकश की और चेतावनी दी कि अगर वे युद्ध नहीं रोकते हैं तो अमेरिका व्यापार रोक देगा। आशय यह था कि उन्होंने व्यापार खत्म करने का दबाव डाल कर दोनों देशों को सीजफायर के लिए राजी किया है। उन्होंने अपनी मध्यस्थता में सीजफायर पर कराया लेकिन भारत ने किसी भरी मध्यस्थता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद इस अधपके सीजफायर ने सरकार के लिए प्रतिकूल स्थिति पैदा की। एक तरफ सीजफायर कों जल्दबाजी में लिया फैसला कहां गया तो दूसरी और इसे अमेरिका के दबाव में आने के बतौर देखा गया। कुछ लोगों का मानना है कि भारत को सीजफायर करने से पहले पाकिस्तान की ओर से कोई ठोस आश्वासन लेना चाहिए था। यहां तक कहा गया कि इससे भारत का इकबाल कमजोर हुआ है। पाकिस्तान में लोकतंत्र बेहद खस्ता हालत में है।

सरकार,में सेना का दबदबा है। सेना के कारण पुर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से बेदखल करके जेल मैं डाल दिया गया है। आतंकवादी समूहों को संरक्षण देना और उनके दबाव में काम करना पाकिस्तान सरकार की विवशता रही है। आतंकियों और सेना के हस्तक्षेप के कारण पाकिस्तान में अस्थिरता बनी रहती हैं। इसलिए ऐसे देश से प्रायोजित आतंकवाद से निपटना भारत जैसे पड़ोसी के लिए वाकई बड़ी चुनौती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जब विपक्ष और परे देश नते पाकिस्तान पर आक्रमण का समर्थन किया तो अचानक सीजफायर क्यों किया गया?

प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मई की रात अपने संबोधन में कहा, 'पाकिस्तान तनाव कम करने की गुहार लगाने लगा, पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया।

पाकिस्तान ने कहा कि अब वह कोई आतंकी गतिविधि नहीं करेगा, तब भारत ने भी विचार किया। इस दावे को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब हमारी सेना ने पाकिस्तान के हौसले पस्त कर दिए थे, तो सीजफायर के जरिए सेना के हाथ क्यों बांधे गए? पाकिस्तान हमारे हवाई हमले रोक नहीं पा रहा था। पाकिस्तान को चाहिए था कि पहलगाम हमले के आतंकी हमें सौंप दे। अगर पाकिस्तान ने युद्ध रोकने का प्रस्ताव दिया तो लिखित समझौता होना चाहिए था। इसके बगैर पहलगांव के पीडितों को न्याय कैसे मिलेगा? इस प्रकरण में अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। मोदी सरकार द्वारा सीजफायर की घोषणा से ठीक पहले ट्रंप के दावे की सच्चाई पूछी जा रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ट्रंप के दावों और व्यापार बंद करने की धमकी के संबंध में भी कोई टिप्पणी नहीं की। यहां तक कि ट्रंप द्वारा कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश पर भी कुछ नहीं कहा जबकि इसे अमेरिका की दखलंदाजी के बतौर देखा जा रहा है।

अमेरिका ने किसी तीसरी जगह पर भारत और पाक प्रधानमंत्रियों की संभावित मुलाकात का दावा भी किया। इस पर भी सवाल पूछे जा रहे है कि मोदी क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल कर राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाले हैं? सोशल मीडिया में सवाल हैं कि हमारी सेना ने पाकिस्तान स्थित आतंकी कैम्प तबाह किए, लेकिन पहलगाम घटना को अंजाम देने वाले आतंकी कब पकड़े जाएंगे। पाक अधिकृत कश्मीर से पाकिस्तान को क्यों नहीं खदेड़ा, यह भी पूछा जा रहा है। जाहिर है कि अचानक सीजफायर ने इन तमाम सवालों को जन्म दिया है। इनका समुचित जवाब भारत सरकार और भाजपा, दोनों को जल्द देना होगा ताकि भ्रमों का निराकरण हो। पाकिस्तान बर्बाद मुल्क है, और ऐसे में उसकी गतिविधियों से देश को सुरक्षित रखते हुए प्रयास जरूरी है कि हम किसी युद्ध की दलदल में न फस जाएं।

सिन्दूर: अब श्रृंगार ही नहीं, शौर्य का प्रतीक

सिन्दूर, जो कभी सिर्फ वैवाहिक प्रेम का प्रतीक था, आज ऑपरेशन सिंदूर की नायिकाओं वियोमिका और सोफिया की साहसिक कहानियों का प्रतीक बन गया है। ये महिलाएं सिर्फ सजी-धजी मूरतें नहीं, बल्कि अदम्य साहस, बलिदान और नारी शक्ति का जीवंत उदाहरण हैं। उन्होंने न केवल अपने हौसले से दुश्मनों को मात दी, बल्कि यह भी दिखाया कि सिन्दूर का यह लाल रंग नारी के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की ज्वाला है। यह सिन्दूर अब केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि संघर्ष, समर्पण और शौर्य की अनूठी कहानी है।



सिन्दूर, जो प्राचीन काल से भारतीय नारी के वैवाहिक जीवन का प्रतीक रहा है, आज एक नए अर्थ में उभर रहा है। यह केवल सुहाग का प्रतीक नहीं, बल्कि नारी शक्ति, साहस और स्वाभिमान का प्रतीक बनता जा रहा है। यह बदलाव केवल एक सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का संकेत है। भारतीय समाज में सिन्दूर का स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह न केवल पति की लंबी उम्र की कामना है, बल्कि पति-पत्नी के बीच के अटूट बंधन का प्रतीक भी है। लेकिन बदलते समय के साथ, सिन्दूर अब केवल एक पारंपरिक श्रृंगार का हिस्सा नहीं रह गया है। यह आज की नारी की स्वतंत्रता, स्वाभिमान और साहस का भी प्रतीक बन चुका है।

प्राचीन ग्रंथों में सिन्दूर को सौभाग्य, प्रेम और आस्था का प्रतीक माना गया है। लेकिन जब हम इतिहास के पन्नों में झांकते हैं, तो हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां सिन्दूर केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि शौर्य और बलिदान का प्रतीक भी बना। रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, पद्मावती जैसी वीरांगनाओं ने अपने सिन्दूर की लाज के लिए तलवार उठाई, अपने प्राणों की आहुति दी। ये उदाहरण दिखाते हैं कि सिन्दूर केवल सौंदर्य का नहीं, बल्कि स्वाभिमान और आत्मबल का प्रतीक भी है। आज की नारी भी इसी भावना से ओतप्रोत है। वह केवल एक पत्नी, मां या बहू तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की रीढ़ है। वह हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है - चाहे वह खेल का मैदान हो, युद्ध का मैदान हो, या फिर राजनीति की गूंज। मिताली राज, मेरी कॉम, नीरज चोपड़ा जैसी खिलाड़ियों ने सिन्दूर के प्रतीक को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनकी सफलता की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सिन्दूर न केवल परिवार का सम्मान है, बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक भी है।

इस भावना को हाल ही में 'ऑपरेशन सिंदूर' ने भी बल दिया, जिसमें वियोमिका और सोफिया जैसी बहादुर महिलाओं ने अपने साहस और संघर्ष से यह साबित किया कि सिन्दूर केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि अदम्य साहस का प्रतीक है। इन वीरांगनाओं ने न केवल अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, बल्कि समाज की धारणाओं को भी चुनौती दी। यह परिवर्तन केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर कोने में महसूस किया जा रहा है। सिन्दूर अब केवल पवित्रता का नहीं, बल्कि प्रतिरोध का प्रतीक भी है। यह उन महिलाओं की आवाज है जो अन्याय के खिलाफ उठ खड़ी होती हैं, अपने हक के लिए लड़ती हैं, और समाज की बंधी-बंधाई धारणाओं को तोड़ती हैं।

यह बदलाव फिल्मों और साहित्य में भी साफ दिखाई देता है। जैसे कि फिल्म 'मणिकर्णिका' में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सिन्दूर केवल श्रृंगार का नहीं, बल्कि स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक है। इसी तरह, कई वेब सीरीज और कहानियां भी सिन्दूर को एक नई परिभाषा दे रही हैं। समाज का यह नया दृष्टिकोण नारी के प्रति उसकी बदलती सोच का प्रतीक है। अब सिन्दूर केवल विवाह का प्रतीक नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया है। यह उस नारी का प्रतीक है जो किसी भी परिस्थिति में न झुकने का संकल्प लेती है, जो अपने आत्मसम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।

संक्षेप में कहें तो, सिन्दूर अब केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि शौर्य का प्रतीक है। यह हर उस नारी का प्रतिनिधित्व करता है जो खुद को परिभाषित करने में सक्षम है, जो किसी भी बंधन को तोड़कर अपनी पहचान बना रही है। यह बदलाव हमारे समाज की सोच में आ रहे सकारात्मक परिवर्तन का सूचक है। यह केवल एक परंपरा का नहीं, बल्कि एक पूरे विचारधारा का पुनर्जागरण है। आज की नारी सिन्दूर को केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि अपने संघर्ष और स्वाभिमान का प्रतीक मानती है। यह उसकी शक्ति, संकल्प और आत्मसम्मान का प्रमाण है। सिन्दूर, जो एक समय केवल वैवाहिक बंधन का प्रतीक था, आज नारी की आत्मशक्ति, संघर्ष और साहस का प्रतीक बन चुका है। यह उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने अपने सपनों को पंख दिए और समाज की पुरानी धारणाओं को तोड़ा।

यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक संकल्प है - खुद को परिभाषित करने का, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने का, और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का। यह उन वीरांगनाओं का प्रतीक है जिन्होंने इतिहास को अपने खून से लिखा और उन आधुनिक नारियों का प्रतीक है जो हर चुनौती को आत्मविश्वास से स्वीकारती हैं। सिन्दूर अब केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि नारीत्व का महाकाव्य है - संघर्ष, स्वाभिमान और शौर्य का प्रतीक।

-प्रियंका सौरभ

दक्षिण-पश्चिम हरियाणा की रेतीली धरती पर, जहां धूप की तल्खी रेत के कणों को भी तपाने में सक्षम होती है, वहीं बसा है बड़वा एक गांव जो आज भी अपने अतीत की स्मृतियों को हवेलियों की दीवारों, तालाबों की गहराई, और चित्रों की रंगरेखा में संजोए हुए है।



बड़वा गांव की हवेलियों में इतिहास की गूंज: ठाकुरों की गढ़ी से केसर तालाब तक

यह गांव भिवानी जिले में, हिसार से 25 किलोमीटर दक्षिण में, राजगढ़-बीकानेर राजमार्ग पर स्थित है। इसकी पहचान सिर्फ एक सामान्य ग्रामीण बस्ती के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित संग्रहालय के रूप में है, जिसमें स्थापत्य, कला, संस्कृति और सामाजिक इतिहास के तमाम रंग समाए हैं।

ठाकुरों की गढ़ी: बड़वा की आत्मा

बड़वा का उल्लेख आते ही सबसे पहले जिस ऐतिहासिक संरचना का नाम आता है, वह है ठाकुरों की गढ़ी। यह गढ़ी गांव के उत्तर-पश्चिम में स्थित एक रेतीले टीले पर बनी है, जिसे ब्रांसा भवन भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1938 में किया गया था – उस समय जब मानसून ने धोखा दिया और गांव में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब ठाकुर बाग सिंह तंवर ने इसे रोजगार के अवसर के रूप में देखा और अपने लोगों को निर्माण कार्य में जुटाया।

गढ़ी का विशाल प्रवेशद्वार आज भी लोहे की मोटी प्लेटों और मजबूत लकड़ी से सुसज्जित है। अंदर प्रवेश करते ही लगता है जैसे हम किसी मध्यकालीन कथा में प्रवेश कर रहे हों। भंडारण के लिए बने कमरों की पंक्तियां, रहने योग्य विशाल हॉल, और हाथीखानों की व्यवस्था आज भी इसकी भव्यता की गवाही देती है।

तंवरों की विरासत:

राजस्थान से हरियाणा तक

बड़वा गांव की नींव तंवर राजपूतों ने रखी थी, जो कि करीब 600 साल पहले राजस्थान के जीतपुरा से यहां आए थे। ठाकुर बृजभूषण सिंह, जो आज इस गढ़ी के उत्तराधिकारी हैं, के पूर्वजों ने यहां 14,000 बीघा भूमि पर अधिकार किया था और धीरे-धीरे इसे एक समृद्ध जागीर में परिवर्तित किया। मुगल काल में तंवरों ने संघर्ष के बजाय शांति और व्यापार को अपनाया, और भिवानी क्षेत्र में अपने लिए एक मजबूत सामाजिक और राजनीतिक स्थान निर्मित किया।

गांव की हवेलियां: जहां दीवारें बोलती हैं

बड़वा में लगभग एक दर्जन ऐतिहासिक हवेलियां हैं, जिनमें से सेठ परशुराम, सेठ हुकुमचंद लाला सोहनलाल और सेठ लक्ष्मीचंद की हवेलियां सबसे अधिक उल्लेखनीय हैं। इन हवेलियों की स्थापत्य शैली, चित्रांकन और दीवारों पर बनी धार्मिक व सांस्कृतिक छवियां राजस्थान की कोटा और किशनगढ़ शैलियों की याद दिलाती हैं। **सेठ परशुराम की हवेली:** इनकी हवेली को पिलानी से लाए गए कारीगरों ने सजाया। हवेली के हर कोने में बारीकी से उकेरे गए चित्र हैं, जो कृष्ण-राधा की रासलीला, राजा-रानी के प्रेम संवाद और धार्मिक कथाओं को दशार्ते हैं।

सेठ हुकुमचंद की हवेली: मुख्य द्वार पर सजे हाथी की आकृति, जिसके ऊपर राजा-रानी विराजमान हैं, दशार्ता है कि कैसे शाही जीवन को इन चित्रों में जीवंत किया गया। दीवारों पर विष्णु लक्ष्मी, शेरावाली माता के चित्र तथा कोटा शैली में बने राधा-कृष्ण के प्रेम प्रसंग दिखाई देते हैं।

लक्ष्मीचंद का कटहरा: इस स्थान पर छतों पर रथयात्राएं, सेविकाएं, और सुरक्षा में चलते सैनिकों के चित्र मिलते हैं। एक दृश्य में श्रीकृष्ण राधा की चोटी गूंथते हुए नजर आते हैं – यह चित्रण उस काल की पारिवारिक निकटता, सौंदर्यबोध और प्रेमाभिव्यक्ति की गहराई को दशार्ता है।

केसर तालाब और 'मुक्तिधाम'

बड़वा गांव की पहचान केसर तालाब से भी जुड़ी है, जो सेठ परशुराम ने अपनी बहन केसर की स्मृति में बनवाया था। कथा कहती है कि जब गांव की स्त्रियां गोबर चुनती थीं, तो यह कार्य उच्च जातियों और सम्पन्न परिवारों के लिए अपमानजनक माना जाता था। बहन को अपमान से बचाने हेतु सेठ ने वहां एक विशाल पक्का तालाब बनवाया, जिसका नाम केसर तालाब पड़ा। इस तालाब के पास एक गहरा कुंड है, जिसे मुक्तिधाम कहा जाता है, क्योंकि दुःखी महिलाएं यहां आत्महत्या के लिए कूदी थीं। इसके किनारे बनी छतरियों की दीवारों पर राधा-कृष्ण की रासलीला के चित्र बने हैं, जिनमें ढोलक, नगाड़े, बांसुरी, हारमोनियम जैसे वाद्ययंत्रों के चित्र भी हैं।

इन चित्रों में लाल, पीले और नीले रंगों का प्रयोग हुआ है। श्रीकृष्ण को नीले और राधा को गोरे रंग में चित्रित किया गया है। पशु-पक्षियों की आकृतियां – मोर, तोता, चिड़ियाँ – भी इसमें देखी जा सकती हैं।

फिल्मों का गांव: 'चंद्रावल' और 'बैरी' की धरती

बड़वा की सांस्कृतिक समृद्धि इतनी प्राचीन और प्रभावशाली रही है कि हरियाणवी सिनेमा भी इससे अछूता नहीं रहा। प्रसिद्ध फिल्म चंद्रावल और बैरी के कुछ दृश्य इसी गांव के रूसहड़ा जोहड़ और कुओं के पास फिल्माए गए। आज भी वे पनघट, जिन पर 'चंद्रो' पानी भरने आती थी, गांववालों की स्मृति और गर्व का विषय हैं।

अतीत की गोद में वर्तमान की पहचान

बड़वा सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि हरियाणा के ग्रामीण गौरव की जीवित मिसाल है। इसकी हवेलियां, चित्रकला, तालाब, धार्मिक धरोहरें और सामाजिक कथाएं – सब मिलकर इसे एक विरासत स्थल बनाती हैं। आज जब विकास की अंधी दौड़ में गांवों का सांस्कृतिक चरित्र खोता जा रहा है, बड़वा जैसे गांव यह सिखाते हैं कि यदि हम अपने अतीत को संजो कर रखें, तो वह न केवल हमारी पहचान को मजबूत करता है बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है।

- डॉ. सत्यवान सौरभ,

भारतीय पत्रकारिता जगत की अपूरणीय क्षति'

के. विक्रम राव का जाना भारतीय पत्रकारिता जगत की अपूरणीय क्षति जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। लेकिन उनके पत्रकारीय जीवन के संघर्ष नई पीढ़ी को प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। उन्होंने विख्यात अखबारों में ही काम नही किया बल्कि वे स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता और लेखन में रत रहे। प्रतिवर्ष लखनऊ प्रेस क्लब में मई दिवस पर पत्रकारों और अखबार कर्मियों का जमावड़ा होता था जो एक मेले जैसा आयोजन होता था। इस बार के विक्रम राव, प्रेस क्लब में मई दिवस पर आये तो व्हील चेयर पर आये और अस्वस्थता के फलस्वरूप उनकी आवाज में वह उसक नहीं दिखी। वहीं चंद दिनों पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ से मुलाकात की आई जब अपनी पुस्तकों को भेंट करने और संभवतः पुस्तकों के विमोचन का समय लेने के लिए अपनी अस्वस्थता के बावजूद गए थे। उस समय वे शरीर से काफी कमजोर लग रहे थे। तेलुगुभाषी दक्षिण भारतीय होना भी उनके जीवन से अंग्रेजी और हिन्दी में उनका लेखन रहा है। वह अपने पीछे परिवार में दो पुत्र, एक पुत्री एवं पत्नी डॉ. सुधा राव जो पेशे से चिकित्सक है के राव ऐसे पत्र कारों के लेखों को उचित नहीं मानते थे जो लिखते अंग्रेजी में थे और अनूदित होकर छपते हिन्दी में थे। वह इससे सहमत नहीं होते थे। वे अंग्रेजी के साथ हिंदी पर भी समान अधिकार रखते थे। यही कारण है कि उनके हिन्दी के लेख अनूदित होकर उनके स्वयं लिखे जाते थे और अंग्रेजी के शब्दों का उपयुक्त हिंदी शब्द भी लिखते थे।

डा. सुमन गुप्ता के अनुसार, मुझे याद है कि कई बार वे अपने मित्र शीतला सिंह को टोक दिया करते थे कि आपका संपादकीय बहुत बड़ा होता है। एक संपादकीय में आप दो तीन संपादकीय लिखा करिए। वे जनमोर्चा के संपादकीय पृष्ठ जरूर पढ़ते थे। जब हम पत्रकारों ने रेडियो से समाचार सुनना छोड़ दिया लेकिन वे हमेशा रेडियो से देश विदेश के समाचार बहुत इत्मीनान से सुना करते थे। भारत के मुद्दों के साथ ही अंतरराष्ट्रीय युद्धों पर भी उनकी गहरी पकड़ थी।

श्रमजीवी श्रमजीवी पत्रकारों के लिए आजीवन संघर्ष काने वाले के. विक्रम राव आज भले ही हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी लेखनी उनके विचार सदैव उनके व्यक्ति की छवि सदैव प्रस्तुत करते रहेंगे। वे हमेशा अपने को एक श्रमजीवी पत्रकार ही मानते रहे।अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के वे मौजूदा अध्यक्ष भी थे। उन्होंने देश-विदेश के पत्रकारों को एकजुट करने और भारतीय पत्रकारों को दुनिया के पत्रकारों से रूबरू कराने का भी काम किया। पत्रकारिता उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता - के. रामा राव नेशनल हेराल्ड के संस्थापक संपादक थे जिसकी स्थापना आजादी से पूर्व पं. जवाहर लाल नेहरू ने की थी। अंग्रेजी अखबार में संवाददाता होने के बावजूद उन्होंने हिन्दी में भी बहुत से लेख लिखे और अपने अंतिम दिनों में भी वे लिखते रहे। उनके लेख निरंतर अखबारों में छपते रहे। वे सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं देश को जाने माने पत्रकार रहे।

कलियुग का स्वयंवर



त्रेता में धनुष उठा था जब,
जनकपुरी थर्राई थी।
धरा काँपी, गगन डोला,
वीरता मुस्काई थी।
राम ने तोड़ा जिसको छूकर,
वह धनुष, वह गर्व पुराना–
आज उसी की जगह लिये हैं,
फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, थाना!



द्वापर का वह दृश्य अनोखा,
जहाँ आँख मछली की थी,
नीचे जल में देख निशाना,
छूटती बाणों की थी।
अर्जुन ने दिखलाई शक्ति,
राजकुमारी हर्षाई,
पर अब की दुल्हन कहती है,
सरकारी में सेलेक्शन आई?
न काल था वह, न स्वर्ग था वह,
न नरक का कोई मेला,
यह कलियुग है, जहाँ प्रेम नहीं,
बस कटऑफ का ही झेला!
ना तप है, ना योग बचा है,
ना ही धर्म के गीत,
अब दूल्हा बनता वो ही है,
जिसके हाथ में हो सीट!
ना राम चाहिए, ना अर्जुन,
ना शिव का कोई रूप,
अब दूल्हा वही बनेगा जो,
निकाले प्री और मेन की धूप।
सीता की जगह अब लड़की पूछे,
ग्रेड-पे क्या है तुम्हारा?
और सास बने इंटरव्यू बोर्ड,
पूछे ह्लक्या है विचार तुम्हारा?
पांडव तप में, राम मर्यादा में,
आज का युवक बस परीक्षा में,
ना धनुष, ना बाण, ना गदा,
लड़ा जा रहा है पोस्टिंग की भाषा में।
वीर नहीं अब बनते रण में,
वीर बनते हैं टियर-वन में!

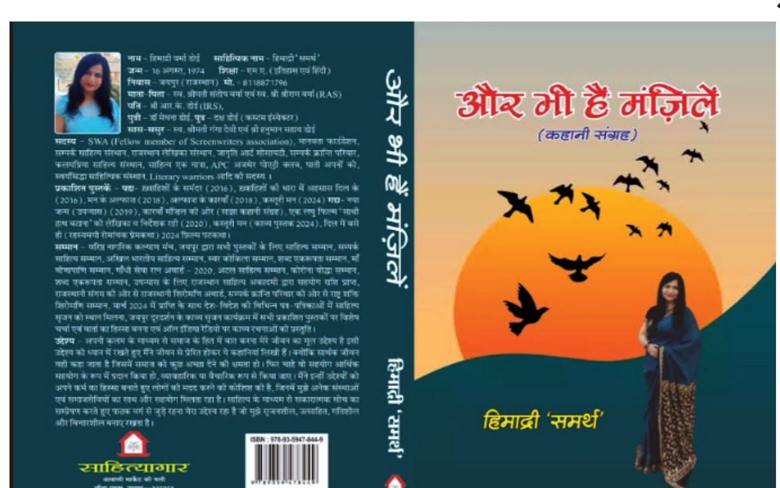
डॉ सत्यवान सौरभ

समाज में व्याप्त, विषमताओं और समस्याओं का समाधान खोजती पुस्तक 'और भी हैं राहें'

लेखिका हिमाद्री 'समर्थ' का कहानी संग्रह 'और भी है मंजिलें' उनकी 9वीं पुस्तक है जिसे उन्होंने अपने सास ससुर को समर्पित कर लिखा है ।आप मानती हैं कि जीवन में जितनी भी खुशहाली और प्रगति आती है वह बड़ों के आशीर्वाद से ही संभव हो पाती है ,जो बिल्कुल सत्य है ।इस कहानी संग्रह की भूमिका में डॉ. दुर्गा प्रसाद अग्रवाल शिक्षाविद एवं वरिष्ठ साहित्यकार लिखते हैं कि हिमाद्री समर्थ की कहानियों में सीधे-सीधे अपनी बात कही है। शुभकामना संदेशों में अविनाश शर्मा कुलसचिव हिंदी प्रचार प्रसार संस्थान जयपुर विश्व विनायक शर्मा , उषा रस्तोगी संतराम पांडेय जी ने लिखे जो प्रेरणास्पद लगे ।मन का मंथन में लेखिका हिमाद्री समर्थ लिखती है कि और भी है मंजिले की कहानी समाज की स्थिति से उत्पन्न समस्याओं का समाधान ढूंढने का एक छोटा सा प्रयास है।

प्रस्तुत कहानी संग्रह करते हुए शिल्प की दृष्टि से सटीक बैठती है घटनाओं की क्रमिकता देखते ही बनती है कथानक की भाषा सरल वोधगम्य है इस कहानी संग्रह में 21 कहानियां है जिसे लेखिका ने व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक मुद्दों ,प्रथाओं ,संघर्ष त्याग ,समर्पण ,नारी विमर्श के मुद्दों से प्रेरित होकर विभिन्न विषयों को कहानी रूप में लिखने का सार्थक प्रयास किया है ।

इन कहानियों से समाज में व्याप्त विषमताओं समस्याओं का चित्रण किया है लेखिका समाज में सकारात्मक बदलाव व नवीन संभावनाओं नए विकल्पों की ओर पाठकों का ध्यान इंगित करना चाहती है ।इस कहानी संग्रह की प्रथम कहानी दमन में दिव्या अपने सपनों का दमन करती है वह अपनी नौकरी का अकेले जीवन यापन करती है वह लिंग जांच के लिए मना करती है। जिसे गुनाह मान लिया जाता है। दमन उसे मानसिक रूप से परेशान करने लगा । वह उसे छोड़कर ससुराल व पीहर को छोड़कर अकेली रहती है । आज भी लोग यह नहीं सोचते हैं कि औरत के बिना पुरुष कहाँ से आएंगे जो पुरुष ऐसी बात करते हैं वह भी औरत के गर्भ से उत्पन्न हुआ है ।कहानी के अंत में दमन अपनी गलती स्वीकार कर लेता है दोनों सुख पूर्वक फिर से अपनी बेटी के साथ रहने लगते



हैं। इस कहानी में लेखिका ने मानवीय संवेदनाओं को लिखने का मार्मिक प्रयास किया है।

कहानी माँ का उपचार में कोरोना काल के लॉकडाउन की घटना को दृष्टिगत रखकर लिखा है कि शहर आकर लोग इंसानी रिश्तों को भूल बैठे हैं ।यह कड़वा सच लेखिका ने बखूबी इस कहानी में लिखा है ।

खो गई मां कहानी में महिमा अपने पारिवारिक दायित्वों को ही अपना कर्म मानती है ।उसके बच्चे उच्च पदों पर सेवारत हैं ।बेटे उन पर ताने मारते हैं ।उसका बड़ा बेटा जो पुलिस में एस आई बना वह कहता है मम्मी आप हमें मत सिखाओ नौकरी कैसे करनी है1? आप तो अपनी रसोई संभालो बड़े भाई की इस बात का छोटा भाई समर्थन करता है। नौकरी और स्कूल की पढ़ाई में दिन-रात का अंतर है ।दोनों की बातें सुन माँ महिमा का काटो तो खून नहीं जैसा हाल था ।वास्तव में आज घरों में बच्चे ऐसा ही व्यवहार करने लगे हैं लेकिन महिमा रात-रात भर जागती है। कहानी के अंत में वह कहती है हेमंत में खोई नहीं हूँ बल्कि मैंने तो खुद को खोज लिया है ,अपनी रसोई की होकर। हेमंत को जवाब देती है मैं अपनी सफलता पर घमंड नहीं स्वाभिमान करती हूँ जो मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अर्जित किया है। लेखिका इस पारिवारिक कहानी में रिश्तो की अहमियत दशार्ती है।

पहनावा कहानी में फैशन का जिक्र किया है ।आज की पीढ़ी कैसे परिधान पहनती है पश्चिम की संस्कृति का अंधानुकरण कितना सही है पति-पत्नी के रिश्ते का सच बखूबी लिखा है। आजकल की युवा पीढ़ी वही करती है जो उनको करना है लेकिन बड़े लोगों को चाहिए कि वह युवा पीढ़ी को गलत काम के दुष्परिणामों से उन्हें आगाह अवश्य करें ।

कामकाजी महिलाओं के घर में कैसी लड़ाइयाँ होती है उसका एक उदाहरण पाखी कहानी में देखा जा सकता है। पाखी कहानी में एक शिक्षिका है जिज पर उसका पति मयूर कितना संदेह करता है उसके चरित्र पर लांछन लगाता है ।उसे ताने मारता है उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है ।मयूर जैसे व्यक्ति के साथ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। वह शराब के नशे में पाखी को बुरा भला कहता है ।जब वह यह सब सुनते सुनते गुस्से में तस्वीर जमीन पर फेंकना शुरू करती है तो उसे समय मयूर उसका वीडियो फोन में बना लेता है और उसे पागल करार देकर सदा के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज देता है।

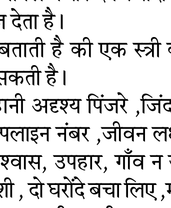
कृतिः-
और भी है मंजिलें
(कहानी संग्रह)
प्रकाशकः-साहित्यागर जयपुर
मूल्यः- 300/-

सौभाग्यवती कहानी बताती है की एक स्त्री को दूसरी स्त्री कमजोर बना सकती है।

कहानी संग्रह की कहानी अदृश्य पिंजरे ,जिंदगी का करतब सिग्नल ,हेल्पलाइन नंबर ,जीवन लक्ष्य ,स्वाभिमान ,गुनहगार विश्वास, उपहार, गाँव न जा सके बापूजी ,उमर की खुशी , दो घरोंदे बचा लिए ,मन का अँधियारा जब छँट गया पठनीय लगी ।

उमर की खुशी में बताया कि धर्म अलग होने पर विवाह को समाज अनुमति नहीं देता है और रिश्ते किस तरह समर्पण से चलते हैं। उमर की खुशी का नायक उमर खुशी के लिए कितना समर्पित भाव से उसे चाहता है यह बताया गया है ।इंसानी रिश्ते जाति व धर्म से ऊपर होते हैं ।

प्रस्तुत कहानी संग्रह हेतु में हिमाद्री समर्थ जी को बधाई देता हूं कि उनकी कहानी आदर्शोन्मुखी व यथार्थवादी सोच पर केंद्रित हैं ।स्त्री की परवशता पर आधारित उनकी कहानी सोचने पर विवश करती है। सामाजिक सरोकारों से जुड़ी सभी कहानियों में लेखिका का अभिव्यक्ति कौशल देखते ही बनता है।



मैं विश्वास करता हूं कि इस कहानी संग्रह की कहानियों से पाठकों के सामाजिक जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आएगा तथा एक स्वस्थ समाज की पुनर्स्थापना होगी।

-डॉ. राजेश कुमार शर्मा पुरोहित
समीक्षक,कथाकार ,साहित्यकार
भवानीमंडी,, जिला - झालावाड़ राजस्थान

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।
संपादक: पंकज धर द्विवेदी
संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com